मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : BHOPAL/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

। वर्ष : 26 । अंक : 08 । अप्रैल 2026।

छत्तीसगढ़ का कोरिया मॉडल बेमिसाल...

आत्मनिर्भरता की लिखी नई इबारत

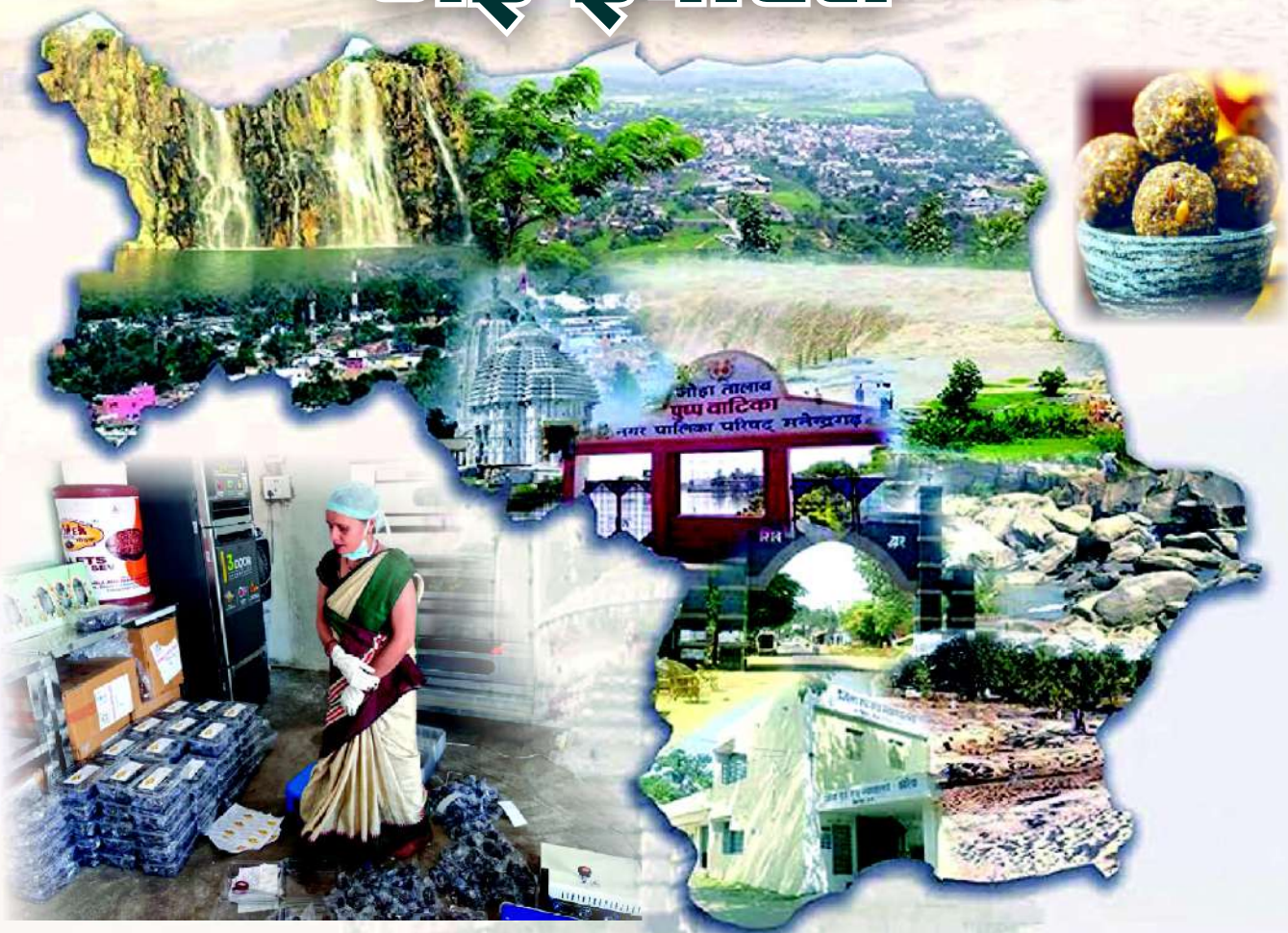

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

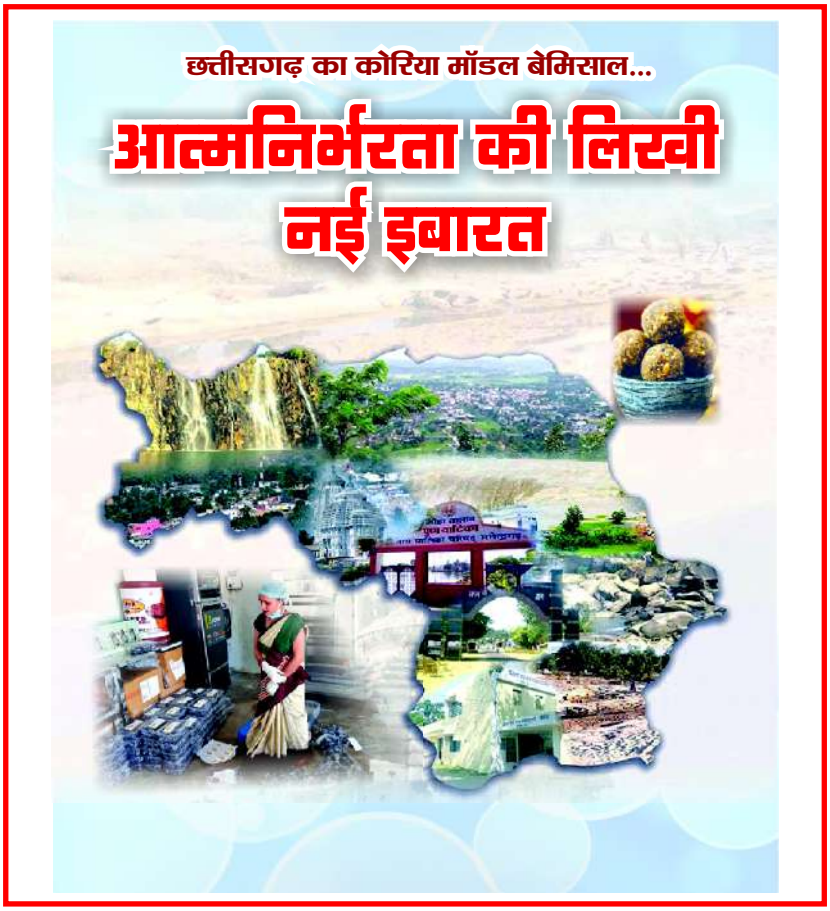

(पृष्ठ क्र.-6)

- महतारी वंदन योजना : आर्थिक संबल से आत्मविश्वास तक, सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं 40
- युद्ध का नया हथियार डिजिटल गड़बड़ी 44
- केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की घटती साख ! 47
- ट्रंप ने विश्व में मचाई तबाही 50
- पारंपरिक मेलों पर संकट 54
- सदियों से समाज में विज्ञान संचार करती आई महिलाएं 56
- इन्दौर में 1857 की क्रांति के नायक 58
- **Jharkhand child marriage crisis: Challenges and a glimer of hope...62**

जान जाए पर मुनाफा न जाए
- सरकार
(विजय:)
सिंगरौली

युद्ध के हालातों के बीच वैश्विक संकट की छाया

ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष एक बहु-आयामी संकट है, जो न केवल मध्य पूर्व में स्थिरता को खत्म कर रहा है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर, मुद्रास्फीति बढ़ाकर और भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाकर एक नए ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर ले जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ा संघर्ष वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सबसे बड़ा भू-राजनीतिक और आर्थिक संकट बन गया है। इस युद्ध के विश्व पर व्यापक और विनाशकारी प्रभाव पड़ रहे हैं। युद्ध भले ही इन तीन देशों के बीच चल रहा है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। युद्ध के कारण विश्व में उथल-पुथल मची हुई है। ईरान द्वारा महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होरमुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने के कारण, दुनिया का 20 प्रतिशत से अधिक तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। इस युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें 100-115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जो इतिहास में तेल आपूर्ति के सबसे बड़े व्यवधानों में से एक है। कच्चे तेल और LNG की कमी के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ गई है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, यदि उच्च तेल कीमतें बनी रहती हैं, तो यह 2026 में वैश्विक GDP विकास दर को 0.3 प्रतिशत तक कम कर सकती है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी आई है। हवाई अड्डे में व्यवधान के कारण हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। एयरलाइंस को मध्य पूर्व के उपर से उड़ानें रोकने या वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे यात्रा का समय और लागत बढ़ गई है।

अमेरिका, इजरायल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, जिसे कई यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ईरान अलग-थलग पड़ रहा है, लेकिन उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।

भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के लिए उर्जा (तेल/गैस) की लागत बढ़ना एक प्रमुख चिंता है। देश के अंदर उर्जा संकट के चलते हायतौबा भी मचने लगी है। गैस की किल्लत सामने आने लगी है। हालांकि अभी पेट्रोल-डीजल को लेकर चिंता की बात नहीं है लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही इस पर भारी असर पड़ने का खतरा मंडरायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद युद्ध के हालातों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और आने वाले समय में खतरे की बात कर चुके हैं। भारतीय एयरलाइंस को भी उड़ानों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें वैकल्पिक रास्तों से जाना पड़ रहा है। होरमुज़ जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण उर्वरक की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जो एशियाई कृषि के लिए बड़ा खतरा है।

ईरान-इजरायल-अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका भले ही बातचीत करने को तैयार दिख रहा है लेकिन ईरान युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है। अमेरिका और इजराईल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यहां तक कि बातचीत करने को भी राजी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह युद्ध कहां आकर रूकता है और इसके कारण विश्व को और कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ का कोरिया मॉडल बेमिसाल...

आत्मनिर्भरता की लिखी नई इबारत

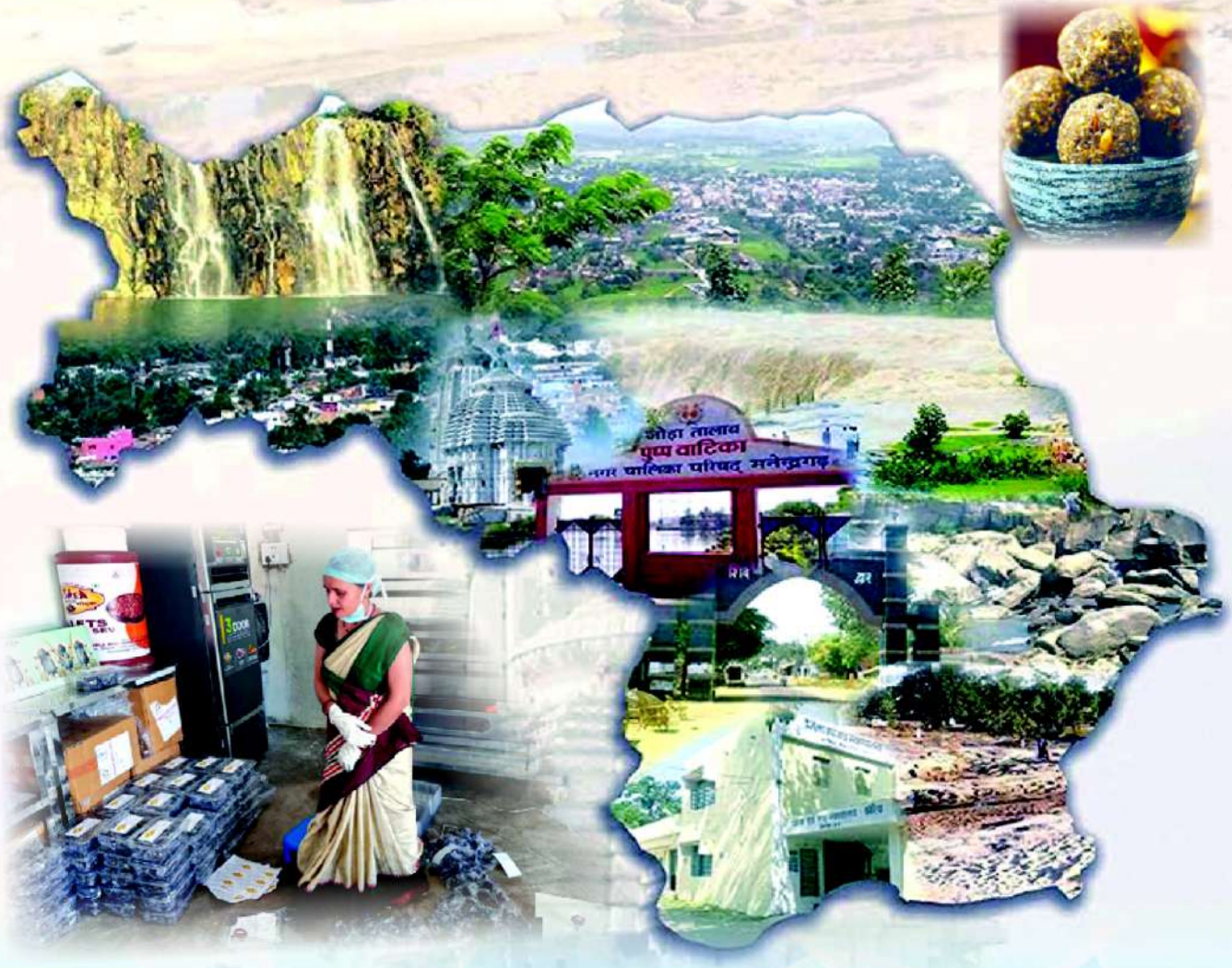

छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला राज्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर यह जिला आज अपने स्थानीय संसाधनों और मेहनत से देश-विदेश में पहचान बना चुका है। शासन-प्रशासन के सहयोग से जिले के निवासी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरिया मॉडल की चर्चा गूंज रही है। आदिवासियों द्वारा निर्मित स्थानीय प्रोडक्ट देश भर में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। कोरिया जिले ने पोषण सुधार और मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। कोरिया मोदक नामक नवाचार ने न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की सेहत संवारने का कार्य किया, बल्कि नवजात बच्चों में कम वजन के जन्म की समस्या को भी आश्चर्यजनक रूप से कम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे है, मातृ स्वास्थ्य, बच्चों के स्वस्थ विकास और समग्र कल्याण को नई दिशा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक शहद सोनहनी की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि यह शुद्धता और मेहनत का ऐसा प्रतीक है, जो न केवल स्थानीय आत्मनिर्भरता को बल देता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को भी मजबूती देता है। कोरिया जिले में बिहान योजना और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। रेडी-टू-ईट, वनोपज प्रसंस्करण और कोरिया मोदक (पोषण लड्डू) जैसे कार्यों से महिलाएं हर साल लाखों की कमाई कर लखपति दीदी बन रही हैं। वहीं जिले में विकसित जल संरक्षण का 05 प्रतिशत मॉडल अब स्थानीय पहल भर नहीं रह गया है, बल्कि देश की राष्ट्रीय जल नीति का हिस्सा बनने जा रहा है। गिरते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट के बीच यह मॉडल जनभागीदारी आधारित समाधान के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसे केंद्र सरकार देश भर में लागू करने की तैयारी कर चुकी है। जिला प्रशासन कोरिया ने डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) की मदद से बुजुर्गों को भीड, लंबी कतारों और परेशानियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से जिला अस्पताल बैकुंठपुर में प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र शुरू किया है। दूसरी तरफ पर्यटन के क्षेत्र में भी जिले ने अपनी अलग पहचान बनाई है। जहां तक जिले में विकास की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियासी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को 97 प्रतिशत लाभ मिला है। शत-प्रतिशत लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार और प्रशासन प्राथमिकता से जिले पर फोकस कर रहा है। खासकर जिला प्रशासन नये नये नवाचार कर अधिक से अधिक लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभांवित कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व से पिछले दो वर्षों में जिले की तस्वीर बदल गई है। विश्व स्तर पर जो छबि जिले की बनी है उसमें मुख्यमंत्री का अहम योगदान है। जगत विजन की टीम ने कोरिया जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर देखा कि कैसे महिलाएं कई व्यवसाय कर आत्मनिर्भर हुई है।

महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और विकास मॉडल के रूप में उभरा कोरिया जिला

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला अब महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णदेव साय के कुशल नेतृत्व और स्थानीय प्रशासक की साझा पहलों से जिले का नाम देश-विदेश में सुर्खियों में है। जिले की व्यवसायी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर आत्म निर्भरता की नई परिभाषा गढ़ी है। कोरिया मोदक लड्डू, सोनहनी शहद और स्थानीय पारंपरिक अचार के व्यवसाय की चर्चाए सारे देश में हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के सहयोग से कई लोग स्वरोजगार की ओर अग्रसर हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर-पश्चिम में बसा कोरिया जिला, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जिले से होकर कई नदियां बहती हैं, जिनमें से कई का उद्गम स्थल भी यहीं है। 25 मई 1998 को ये जिला अस्तित्व में आया कोरिया जिला पहले सरगुजा जिले का ही एक हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे एक अलग जिला बनाया गया। वही दूसरी तरफ देखा जाये तो कोरिया एक आदिवासी बहुल जिला है। कोल, गोंड, गड़ेरी (गड़रिया) जैसी जनजातियां यहां निवास करती हैं। किसी भी जिले के विकास की कहानी अक्सर दो तरह की सोच के बीच चलती दिखाई देती है, पहली सोच वह होती है जिसमें प्रशासन का लक्ष्य जिले और जनता का वास्तविक

मुख्यमंत्री विष्णदेव साय के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिले में विकास की रफ्तार तेज हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना जैसी बुनियादी सुविधाओं का स्थानीय लोगो को शत-प्रतिशत लाभ मिल रहा है। वर्तमान सरकार के सहयोग के कारण ही आज जिला अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है।

विकास होता है, दूसरी सोच वह होती है जिसमें विकास के नाम पर कई चमकदार तस्वीरें जरूर बनती हैं, लेकिन उनके पीछे कभी-कभी व्यक्तिगत ख्याति, प्रशंसा और पदोन्नति की संभावनाएं भी झलकने लगती हैं। कोरिया जिले का विकास होना बेहद जरूरी है और यह स्वागत योग्य भी है, लेकिन विकास की असली पहचान वही होती है जो जमीन पर दिखाई दे और लंबे समय तक टिके, अगर विकास की तस्वीरें केवल प्रस्तुतियों, कार्यक्रमों और रिपोर्टों तक सीमित रह जाएं तो वह विकास नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रदर्शन बनकर रह जाता है, लेकिन कोरिया जिला में ऐसा नहीं है। जिले के समग्र विकास के लिए नई सोच और योजनाओं के साथ काम कर रहा है।

"सांस्कृतिक विरासत को संभालने और निखारने का काम किया कोरिया ने"

यह भी सच है कि जिले का विकास कभी पूरी तरह रूका नहीं, हर कलेक्टर अपने साथ कुछ नए विचार, कुछ नए प्रयोग और कुछ प्रशासनिक पहल लेकर आया, किसी ने शिक्षा पर ध्यान दिया, किसी ने सड़क और भवन निर्माण को प्राथमिकता दी, तो किसी ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की, कई कलेक्टरों के कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि उनके निर्णयों का असर सीधे जनता के जीवन में दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ विकास की परिभाषा भी बदलती दिखाई दी, अब कई बार विकास का मतलब रिकॉर्ड, मॉडल और प्रस्तुतियों की चमक से भी जोड़ा जाने लगा। प्रशासनिक स्तर पर यह कहा जा रहा है कि जिले में कई

जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक और कार्यकारी संपादक समता पाठक ने बैकुण्ठपुर विकासखंड के ग्राम आनी में पहुंचकर कोरिया मोदक लड्डू यूनिट का भ्रमण किया। इस दौरान विजया पाठक ने इस यूनिट में काम करने वाली महिलाओं से विस्तृत चर्चा की ओर इस व्यवसाय के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी ली।

ऐसे कार्य हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए, ऐसा माहौल बना है मानो जिले में विकास की गंगा-जमुना बह रही है।

कोरिया जिला, उत्तर-पश्चिम में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से, दक्षिण में कोरबा जिले से, पूर्व में सूरजपुर जिले से घिरा है। जिले का क्षेत्रफल 5,977 वर्ग किमी है, जिसमें से 59.9 प्रतिशत वन क्षेत्र

जिले में कई ऐसे कार्य हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए, ऐसा माहौल बना है मानो जिले में विकास की गंगा-जमुना बह रही है।

है। यह जिला पर्वत श्रृंखलाओं का एक विशाल समूह है। निचली टेबललैंड की सामान्य उंचाई समुद्र तल से 550 मीटर है। जिले की सबसे उंची चोटी देवगढ़ है, जो 1027 मीटर उंची है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोरिया जिले की जनसंख्या 658,917 है। जिले का जनसंख्या घनत्व 100 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है।

साक्षरता दर 71.41 फीसदी है। जिले की 68.07 प्रतिशत आबादी सरगुजिया बोली और 20.62 प्रतिशत हिंदी बोलती है। इस जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र है। ग्राम 286 हैं। छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और शानदार जलप्रपातों से समृद्ध है, जो इसे पर्यटन के लिए एक प्रमुख स्थल बनाते हैं। इसे 'छत्तीसगढ़ के कश्मीर' के रूप में भी जाना जाता है। प्रमुख आकर्षणों में अमृतधारा, रामदहा जलप्रपात, झुमका बांध और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

कोरिया जिला अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैविक खेती के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध, प्राकृतिक और जैविक सोनहनी के लिए भी जाना जाएगा।

सोनहनी शहद से कोरिया में मीठी क्रांति

कोरिया जिला अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैविक खेती के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध, प्राकृतिक और जैविक सोनहनी के लिए भी जाना जाएगा। यह संभव हुआ है जिला प्रशासन, कृषि विज्ञान केंद्र और स्थानीय किसानों की साझेदारी से, जहां आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक, इटालियन मधुमक्खियों और शुद्ध पर्यावरण ने एक नई क्रांति की नींव रखी है।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं के साथ जगत विजन की संपादक विजया पाठक

दृष्टि, दिशा और दस्तक: यह परियोजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई। जिला प्रशासन ने किसानों को हरियाणा के कुरु क्षेत्र स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र भेजा, जहां 20 किसानों ने सात दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन 20 किसानों का चयन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में फूलों के उपलब्धता, जैविक खेती का क्षेत्रफल एवं कृषकों के रूचि के आधार पर सर्वे के द्वारा किसानों का चयन किया गया। इन किसानों को 25-25 मधुमक्खी पेटियां दी गईं, जिनमें झारखंड से लाई गई इटालियन मधुमक्खियों को बसाया गया।

कोरिया जिला पहले से ही जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां की जलवायु, प्रदूषण रहित वातावरण और फूलों की भरपूर विविधता मधुमक्खियों के लिए आदर्श है।

सोनहनी शुद्धता का प्रतीक: इटालियन मधुमक्खियाँ न केवल अधिक उत्पादन देती हैं, बल्कि इनसे प्राप्त शहद की गुणवत्ता भी बेहतरीन होती है। एक पेटी से सालाना 30 से 50 किलो तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। अन्य बड़े ब्रांडों की तुलना में यह शहद पूरी तरह जैविक है। बिना मिलावट, रंग या कृत्रिम शर्करा के फूलों की विविधता के कारण शहद का रंग और स्वाद भी भिन्न होता है। संतरें के फूल से हल्का शहद तो जंगल के फलों से गाढ़ा एम्बर रंग का शहद प्राप्त होता है।

कोरिया की जलवायु बनी वरदान: कोरिया जिला पहले से ही जैविक खेती के

कोरिया मोदक से महिलाएं हुई आत्मनिर्भर

पोषण, रोजगार और सामाजिक एकत्ता का संगम-कोरिया मोदक

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से महिला शक्ति, सामाजिक एकता और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधार की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। यहां ग्रामीण महिलाओं ने अपने सामूहिक प्रयास से न केवल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, बल्कि समाज में सहयोग, समर्पण और आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम आनी में ज्योति महिला स्व-सहायता समूह और माँ शारदा स्व-सहायता समूह की महिलाएं कोरिया मोदक नामक पौष्टिक लड्डू तैयार कर रही हैं, जिन्हें गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अभिनव पहल से जिले में कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की समस्या को कम करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं के साथ
जगत विजन की संपादक विजया पाठक

सामाजिक सदभाव की मिठास: इस पहल की एक और खास बात यह है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय की महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं। अलग-अलग धर्म, जाति और समुदाय से आने वाली महिलाएं जब एक साथ बैठकर इन पौष्टिक लड्डुओं का निर्माण करती हैं, तो वह केवल पोषण नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश भी समाज तक पहुंचाती हैं।

समस्या से समाधान तक का सफर: कोरिया जिले में लंबे समय से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के जन्म की समस्या चिंता का विषय रही है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त और संतुलित पोषण न मिलने के कारण माताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और नवजात शिशुओं का जन्म वजन भी कम होता था।

कम समय में असरदार व सकारात्मक परिणाम: इसी चुनौती से निपटने के लिए फरवरी 2025 में कोरिया मोदक पहल की शुरुआत की गई। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार कुपोषण उन्मूलन की दिशा में जिला प्रशासन ने विशेष प्रयास किए। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला खनिज न्यास निधि के माध्यम से इस अभिनव योजना को लागू किया गया। यह पहल स्थानीय संसाधनों और महिलाओं की भागीदारी पर आधारित एक ऐसा मॉडल बनकर उभरी है, जिसने कम समय में ही सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया है।

मातृ पोषण को मिला नया आधार: इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के पांचवें माह से लेकर प्रसव तक गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दो पौष्टिक

लिए प्रसिद्ध है। यहां की जलवायु, प्रदूषण रहित वातावरण और फूलों की भरपूर विविधता मधुमक्खियों के लिए आदर्श है। कृषि विज्ञान केंद्र, कोरिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक कमलेश सिंह के अनुसार, अक्टूबर से मार्च तक का समय मधुमक्खी

कोरिया मोदक लड्डू दिए जाते हैं। इन लड्डुओं को मौसम और उपलब्धता के आधार पर रागी, सत्तू, गुड़, मूंगफली, तिल, चना, जौ और घी जैसी पौष्टिक सामग्री से तैयार किया जाता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से तैयार यह लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आयरन, प्रोटीन और उर्जा का समृद्ध स्रोत बन गया है।

समन्वय व संवेदनशीलता: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पोषण संगवारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला को नियमित रूप से इन लड्डुओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही घर-घर जाकर महिलाओं को इनके सेवन के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिससे मातृ पोषण के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है।

सकारात्मक परिणामों ने बढ़ाया भरोसा: कोरिया मोदक पहल के प्रभाव से जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। इस पहल के परिणामस्वरूप कम जन्म वजन वाले शिशुओं के मामलों में लगभग 57 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं 95.9 प्रतिशत नवजात शिशुओं का जन्म वजन 2.5 किलोग्राम से अधिक पाया गया है, जो बेहतर मातृ पोषण का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रारंभिक एएनसी पंजीयन और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया गया है। वहीं 90 प्रतिशत से अधिक कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं में संतोषजनक वजन वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि यदि स्थानीय स्तर पर सही रणनीति और सामुदायिक भागीदारी के साथ प्रयास किए जाएं, तो कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सकता है।

महिलाओं को मिला आर्थिक सशक्तीकरण: इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण का अवसर मिला है। ज्योति और माँ शारदा स्व-सहायता समूह की लगभग 22 महिलाएं प्रतिदिन 5,000 से 6,000 कोरिया मोदक लड्डू तैयार कर रही हैं। अब तक 18 लाख से अधिक लड्डू वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्य से प्रत्येक महिला को प्रतिमाह लगभग 10 से 12 हजार रु पये की आय हो रही है। यानी एक वर्ष में उन्हें एक से डेढ़ लाख रु पये तक की आय प्राप्त हो रही है। इससे महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ सम्मानजनक आजीविका का अवसर भी मिला है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान: कोरिया मोदक पहल की सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। इस अभिनव मॉडल की प्रशंसा नीति आयोग ने भी की है। आयरन और प्रोटीन से भरपूर ये लड्डू गर्भवती महिलाओं में एनीमिया कम करने और नवजात शिशुओं के कम वजन की समस्या को दूर करने में प्रभावी साबित हो रहे हैं। इस पहल को नीति आयोग की स्पेरियेशनल टाइम्स न्यूज़लेटर में स्थान मिला है और इसे आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्केलेबल बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में भी सराहा गया है। समूह से जुड़ी महिलाओं यास्मीन, सविता सिंह, नेहा तिर्की और प्रभा का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वे आने वाली पीढ़ी को जन्म से पहले ही स्वस्थ और मजबूत बनाने में योगदान दे रही हैं। नि:स्संदेह, कोरिया मोदक केवल एक लड्डू ही नहीं बल्कि पोषण, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक एकता की मजबूत नींव बन चुका है। कोरिया जिले की यह पहल आने वाले समय में अन्य जिलों और राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकती है।

पालन के लिए सबसे उपयुक्तहै।

तकनीक और प्रशिक्षण के साथ आगे

बढ़ते किसान: शहद निकासी के लिए किसानों को एक्सट्रैक्टर मशीन दी गई है। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सरसों, धनिया और रामतिल के बीज भी

दिल्ली पहुंचा कोरिया का स्वाद : देश की राजधानी में कोरिया के सोनहनी शहद और अमृत मोदक की भारी मांग

सोनहनी शहद यूनिट का अवलोकन करती विजया पाठक

सरस मेले में जिले के दो स्व-सहायता समूहों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ज्योति महिला स्व-सहायता समूह ने 200 किलोग्राम से अधिक कोरिया अमृत मोदक की बिक्री कर 88 हजार रूपए की आय अर्जित की तथा जागृति महिला स्व-सहायता समूह ने 260 किलोग्राम अचार तथा 36 किलोग्राम पापड़-बड़ी का विक्रय कर एक लाख रूपए से

नि:शुल्क दिए गए हैं, जिससे मधुमक्खियों को पराग स्रोत मिल सके। पैकेजिंग का कार्य स्थानीय स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को भी आजीविका का अवसर मिल रहा है। वर्तमान में 300 ग्राम सोनहनीश शहद की कीमत 175

अधिक की आय प्राप्त की। मेले में उपस्थित विभिन्न विक्रेताओं, खरीदारों और पर्यटकों ने कोरिया जिले के उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद की सराहना करते हुए भविष्य में ऑर्डर देने की इच्छा भी जताई। जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक विधियों से तैयार किए गए उत्पादों को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचा रही हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। जिला प्रशासक जिले की स्व-सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के पारिवारिक और शैक्षणिक वातावरण को भी सशक्त बनाना है।

स्वास्थ्य, समर्पण और स्व सहायता का अनूठा संगमः छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले ने पोषण सुधार और मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। कोरिया मोदक नामक नवाचार ने न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की सेहत संवारने का कार्य किया, बल्कि नवजात बच्चों में कम वजन के जन्म की समस्या को भी आश्चर्यजनक रूप से कम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे है, मातृ स्वास्थ्य, बच्चों के स्वस्थ विकास और समग्र कल्याण को नई दिशा मिल रही है। पोषण पुनर्वास केंद्रों में माताओं और बच्चों के लिए समर्पित देखभाल, स्वच्छता जागरूकता, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के मंशानुरूप जिले में डीएमएफ मद से फरवरी 2025 से कोरिया मोदक निर्माण करने जैसे नवाचार प्रारंभ की है। अब तक दो हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दो कोरिया मोदक लड्डू दिए जा चुके हैं। इस पहल से महिलाओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, साथ ही कम वजन वाले बच्चों (एलबीडब्ल्यू) की जन्म दर में 15 प्रतिशत से घटकर 05 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।

रूपए रखी गई।

जंगल का शहद, पोषण से भरपूरः यहां तैयार शहद सिर्फ पारंपरिक फूलों से नहीं, बल्कि महुआ, पलाश, अर्जुन, नीम, हर्रा-बहेड़ा जैसे औषधीय पेड़ों से भी एकत्र होता है, जिससे यह खनिज और एंटी ऑक्सीडेंट

जगत विज़न पत्रिका की संपादक विजया पाठक मधुमक्खी पालन यूनिट का अवलोकन कर इस यूनिट में काम कर रहे लोगों से बात-चीत करती हुई

से भरपूर होता है।

30 हजार की बिक्री, आत्मनिर्भरता की ओर कदम: शुरूआती चरण में किसानों ने दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक स्थानीय बाजारों व बिहान मेला में लगभग 30,000 रूपए का शहद बेचा है, जिसकी आय उन्हें समान रूप से वितरित की गई। यह पहल जिला खनिज न्यास संस्थान की मदद से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका को सशक्त बनाना है।

मीठा भविष्य बना रहा कोरिया को अग्रणी: यह पहल न केवल किसानों को आत्मनिर्भर

सोनहनी शहद की मिठास पहुंची प्रधानमंत्री तक

मुख्यमंत्री साय के प्रयासों से कोरिया के किसानों को मिली राष्ट्रीय पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक शहद सोनहनी की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि यह शुद्धता और मेहनत का ऐसा प्रतीक है, जो न केवल स्थानीय आत्मनिर्भरता को बल देता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को भी मजबूती देता है। मोदी ने कहा कोरिया जिले के किसानों ने सोनहनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वह शहद जेम पोर्टल समेत अनेक ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न केवल छत्तीसगढ़, बना रही है बल्कि कोरिया जिले को शुद्ध शहद उत्पादन में अग्रणी भी बना रही है। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सोनहनी शुद्धता का प्रतीक बनेगी और इससे जिले को एक नई पहचान मिलेगी। परिश्रम, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से बदलती तस्वीर निश्चित ही सोनहनीश न सिर्फ शहद है, बल्कि यह कोरिया के किसानों के आत्मविश्वास, नवाचार और बदलाव की कहानी है। आने

परिश्रम, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से बदलती तस्वीर निश्चित ही सोनहनीश न सिर्फ शहद है, बल्कि यह कोरिया के किसानों के आत्मविश्वास, नवाचार और बदलाव की कहानी है।

बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी हजारों महिलाएं और युवा हनी उद्यमी बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब शहद की मात्रा के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता और शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ स्टार्टअप्स, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से शहद की शुद्धता को प्रमाणित करने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया अगली बार जब भी शहद खरीदें, तो कोशिश करें कि किसी लोकल किसान या महिला उद्यमी से खरीदें। क्योंकि उस हर बूंद में भारत की मेहनत और उम्मीदें घुली होती हैं। शहद की यह मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। सोनहनी शहद की सराहना कोरिया जिले के किसानों के लिए न केवले गर्व की बात है, बल्कि यह देशभर के जैविक उत्पादकों के लिए भी कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनहनी शहद का मन की बात में जिक्र किया है।

वाले वर्षों में यह पहल न केवल स्थानीय बाजार, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मिठास बिखेरेगी।

बिहान से जुड़ीं महिलाएं बनीं पोषण की

यह पहल न केवल स्थानीय बाजार, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मिठास बिखेरेगी।

वाहक: बैकुंठपुर ब्लॉक के ग्राम आनी में ज्योति स्व-सहायता समूह और माँ शारदा समूह की 25 महिलाओं ने इस योजना को गति दे रही है। सत्तू गुड़, मूंगफली, तिल,

जब जुनून मिला योजना से, जन्मी एक उद्यमी

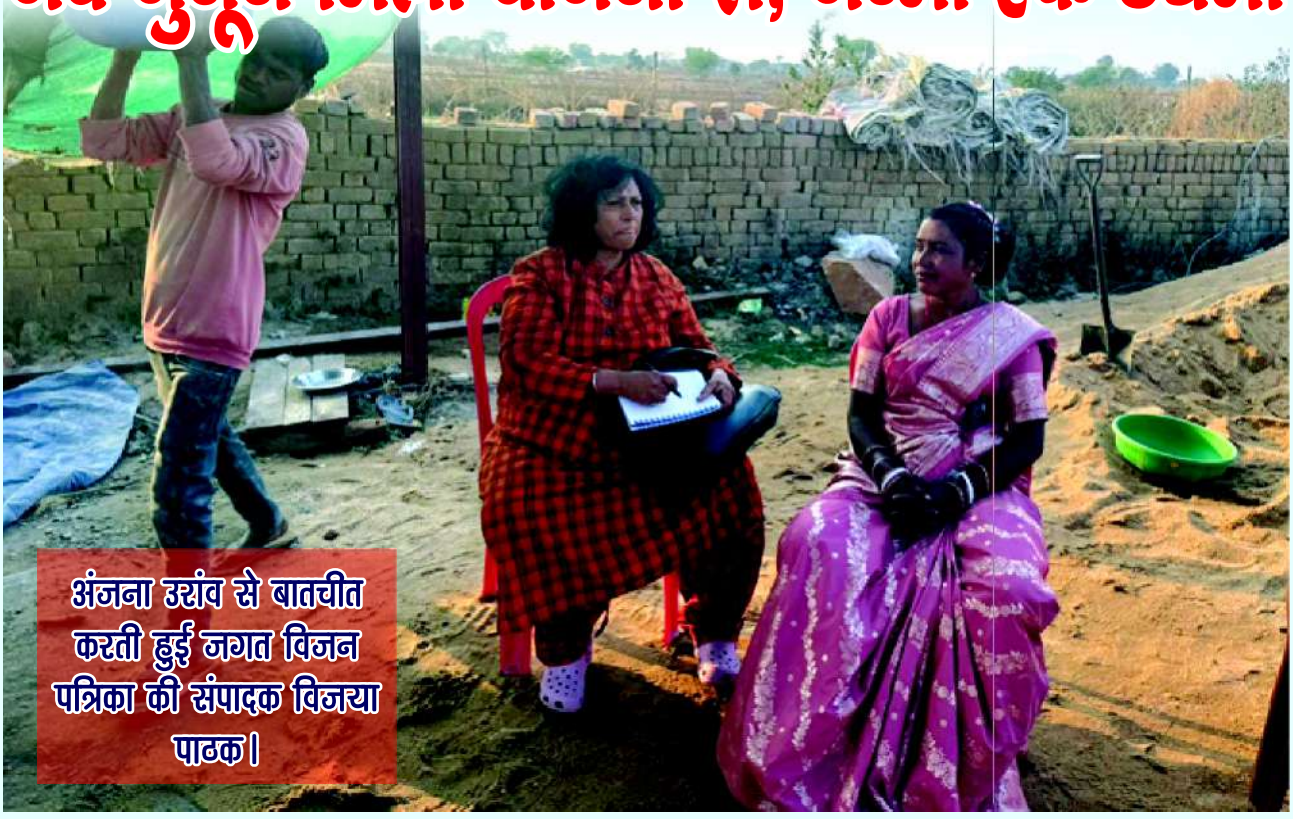

अंजना उरांव से बातचीत करती हुई जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक।

कभी-कभी जीवन की दिशा बदलने के लिए किसी बड़े मंच, बड़े अवसर या बड़े सत्ताधन की आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी एक डस्टबिन में पड़ा कागज का टुकड़ा भी जीवन का करवट बदल देता है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखण्ड के ग्राम तोलगा की अंजना उरांव की कहानी इसी सच्चाई को सशक्त रूप से सामने रखती है। अंजना उरांव कोई उद्योगपति परिवार से नहीं आतीं, न ही उनके पास पूंजी, सिफारिश या विशेष प्रशिक्षण था। वे जनपद पंचायत खड़गवां में एक अंशकालिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। जीवन एक तयशुदा सीमित दायरे में चल रहा था, तभी एक दिन कार्यालय के डस्टबिन में उन्हें एक फटा हुआ पन्ना मिला। उस पन्ने पर लिखा था प्रधानमंत्री सृजन स्वरोजगार योजनाश। वह पन्ना कचरा नहीं था, वह संभावना थी। अंजना ने उसे पढ़ा, समझा और उसी क्षण मन में यह निश्चय किया कि वे सिर्फ नौकरी करने वाली नहीं, बल्कि कुछ सृजित करने वाली बनेंगी। योजना की जानकारी लेने जब उन्होंने जनपद कार्यालय में चर्चा की तो अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ मिली। किसी ने जिला उद्योग केंद्र जाने की सलाह दी, तो किसी ने यह कहकर हतोत्साहित किया कि बैंक और योजनाओं के चक्कर में पड़ना बेवकूफी है। लेकिन अंजना ने

जौ, चना और घी से बने ये स्वादिष्ट व पौष्टिक लड्डू मौसम अनुसार तैयार किए जाते हैं। प्रतिदिन 1500 से 2000 कोरिया मोदक तैयार कर रही है, अब तक 03 लाख से अधिक लड्डू वितरित कर चुके हैं और प्रत्येक महिला को 10-12 हजार मासिक

हार नहीं मानी। अंजना ने जब जिला उद्योग केंद्र से जानकारी लेने के बाद जब पोडी-बचरा क्षेत्र में पलाईऐश ईंट निर्माण इकाई देखी तो उनके भीतर एक उद्यमी जन्म लेने लगा। उन्होंने तय किया कि वे भी पलाईऐश ईंट उद्योग स्थापित करेंगी।

पति का साथ बना ताकतः ऐसे समय में उनके पति अनिल कुमार उनके सबसे बड़े सबल बने। दसवीं तक पढ़े अनिल कुमार को उद्योग का अनुभव नहीं था, लेकिन मेहनत, खेती और परिवार की जिम्मेदारी निभाने का जज्बा भरपूर था। उन्होंने अंजना के सपने को अपना सपना बना लिया।

आज अजना उरांव की अंजना इंटरप्राइजेज फ्लाईऐश ईंट इकाई लगातार उत्पादन कर रही है। अब ईंटों की मांग बढ़ती जा रही है। अंजना उरांव निश्चित ही उन महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जो साधनों और संसाधनों के अभाव का हवाला देकर आगे बढ़ने से रूक जाती हैं। सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ लेकर एक सफल उद्यमी बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही अंजना पर गर्व किया जाना चाहिए। अंजना उरांव की यह कहानी सिर्फ एक महिला उद्यमी की सफलता नहीं है। यह कहानी है सरकारी योजनाओं के सही उपयोग, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत की जमीनी तस्वीर और उस सोच की, जो अवसर को कचरे में भी खोज लेती है।

आमदनी हो रही है यानी 5 माह में 60 हजार रूपए तक लाभ हुआ है। यह नवाचार महिलाओं के लिए आजीविका का नया जरिया भी बन गई है। लड्डू केवल उन्हीं महिलाओं को दिए जाते हैं, जो गर्भावस्था के पांचवें महीने में प्रवेश कर चुकी हों।

प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्रः सेहत, सेवा और सद्भाव की मिसाल

बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र में विजया पाठक।

कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य होता है। इसी सोच को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ के सुदूर कोरिया जिला में बुजुर्गों के लिए एक अनूठी पहल की गई है। जिला प्रशासन कोरिया ने डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) की मदद से बुजुर्गों को भीड, लंबी कतारों और परेशानियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से जिला अस्पताल बैकुंठपुर में प्रदेश का पहला बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र शुरू किया है।

पोषण सगवारी कार्यकर्ता घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं को लड्डू सेवन के लिए प्रेरित कर रहे है। इसका असर अब स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी साफ नजर आने लगा है। इस तरह एलबीडब्ल्यू 8.16 प्रतिशत से घटकर 5.33 प्रतिशत हो गया, कम वजन वाली

यहां जांच, इलाज, दवा और परामर्श एक ही छत के नीचे नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अस्पताल में घुटनों के दर्द, कमजोरी और अन्य उम्रजनित समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्ग ईलाज करा रहे हैं। जिला अस्पताल के एक हाल को बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया। डीएमएफ के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस केंद्र में फिजियोथेरेपी, पंचकर्म, फुट मसाज सहित अन्य उपचार सेवाएं उपलब्ध हैं। यह केंद्र ट्रिपल एस मॉडल सेहत, सेवा और सद्भाव पर संचालित हो रहा है। बुजुर्गों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार ही उनकी सच्ची देखभाल है और यही हमारी सस्कृति की पहचान है। करीब 1700 बुजुर्गों की जांच और उपचार किया जा चुका है। इनमें 977 महिला और 702 पुरूष मरीज शामिल हैं। अब तक 675 मरीजों ने पंचकर्म, 1350 मरीजों ने फिजियोथेरेपी का लाभ लिया है। 500 मरीजों की लैब जांच की गई है तथा 1250 मरीजों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गई हैं। लाभार्थी बुजुर्गों ने बताया कि इलाज से उन्हें राहत मिली है और अस्पताल स्टाफ का व्यवहार बेहद सहयोगात्मक और संवेदनशील है। यह बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल केंद्र न केवल कोरिया जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनकर उभरा है जहां सेहत के साथ सेवा और सद्भाव की भी मिसाल कायम हो रही है।

गर्भवती महिलाओं की संख्या 18 से घटकर 16 हो गई। एलबीडब्ल्यू प्रतिशत में 14.49 प्रतिशत से घटकर 6.09 प्रतिशत की गिरावट आयी है। वहीं कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं की सख्या भी 77 से घटकर 60 हो गई है।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का 05 प्रतिशत जल संरक्षण आधारित मॉडल

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में विकसित जल संरक्षण का 05 प्रतिशत मॉडल अब स्थानीय पहल भर नहीं रह गया है, बल्कि देश की राष्ट्रीय जल नीति का हिस्सा बनने जा रहा है। गिरते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट के बीच यह मॉडल जनभागीदारी आधारित समाधान के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसे केंद्र सरकार देश भर में लागू करने की तैयारी कर चुकी है। कोरिया जिले का 05 प्रतिशत मॉडल अपनी सफलता, जनसहभागिता और प्रभावी परिणामों के कारण सबसे अलग नजर आया, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी।

कैसे काम करता है कोरिया का 05 प्रतिशत मॉडल?: इस पहल की सबसे बड़ी ताकत रही किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर किसानों को समझाया गया कि यदि वे अपनी कृषि भूमि का केवल 05 प्रतिशत हिस्सा जल संरचना (जैसे- सोख्ता गड्ढे, माइक्रो स्टोरेज) के लिए सुरक्षित रखें, तो इसका सीधा फायदा पूरी फसल पर पड़ेगा। बैकुंठपुर और सोनहत क्षेत्र के गांवों में कई किसानों ने खेतों के कोनों में सीढ़ीनुमा सोख्ता गड्ढे

कलेक्टर की संवेदनशील पहल बनी पोषण क्रांति का आधारः कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जब वे यहां पदस्थ हुई तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, साफ पेयजल, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ कुपोषण के खिलाफ खासकर कम

बनाए। इससे बरसात का पानी रूकने लगा और जमीन में तेजी से समाने लगा। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी में नमी बढ़ी, सिंचाई की जरूरत कम हुई और फसलों की सेहत में स्पष्ट सुधार दिखा। यही बदलाव देखकर आसपास के गांवों के किसानों ने भी इस मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया।

आवा पानी झोंकी अभियान से शुरू हुआ प्रयोग बना मिसाल: जल संरक्षण का यह मॉडल आवा पानी झोंकी अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसकी खासियत है कि इसमें न बड़े बांध की जरूरत, न भारी मशीनरी की मांग और न महंगा बजट है। सिर्फ जागरूकता, सामूहिक श्रम और समुदाय की इच्छाशक्ति के दम पर बड़े परिणाम देखने को मिले।

बड़े पैमाने पर लागू होगा तो बनेगा भारत का जल कवच: यह मॉडल बड़े स्तर पर लागू हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण, जल आत्मनिर्भरता और जल संकट समाधान में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। कोरिया जिले की यह पहल अब गांवों की उपलब्धि भर नहीं रह गई है, बल्कि ग्रामीण भारत की सामूहिक शक्ति और नवाचार का प्रतीक बन चुकी है। किसानों की छोटी पहल से शुरू हुई यह सोच अब देश की जल नीति को दिशा देने वाली पहल के रूप में उभर रही है, और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। 05 प्रतिशत मॉडल जल संकट के समाधान के रूप में पूरे देश में धूम मचा रहा है। इस मॉडल के तहत, किसान स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि का 05 प्रतिशत हिस्सा वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए छोटे तालाबों या गड्ढों के निर्माण हेतु देते हैं। मुख्य रूप से जल संचय जन भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है, जो आवा पानी झोकी आंदोलन के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। इसमें किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन का 5 प्रतिशत हिस्सा रिचार्ज स्ट्रक्चर (तालाब/गड्ढे) के लिए दे रहे हैं। यह मॉडल 440 से अधिक पुराने तालाबों के पुनरूद्धार और नीर नायिकाओं (महिला वालंटियर्स) के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण से टिकाउ विकास को बढ़ावा दे रहा है।

वजन वाले बच्चों के जन्म दर को कम करने की रणनीति तैयार की और उसी रणनीति का हिस्सा रहा है कोरिया मोदक लड्डू। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण देना जरूरी है, ताकि अगली पीढ़ी स्वस्थ और सबल हो। कोरिया

विज्ञान और सामुदायिक भावना का संगम है 05 प्रतिशत मॉडलः श्रीमति चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर, कोरिया

यह पहल केवल ढांचों तक सीमित नहीं है। यह हमारे किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने, पलायन को कम करने और हर गांव में भरोसेमंद जल उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़ी है। कोरिया जिला इस गति को बनाए रखते हुए सतत विकास के नए मानक स्थापित करेगा। जिला प्रशासन ने सूक्ष्म जलसंभर मानचित्रण, जलभूवैज्ञानिक आंकलन और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से इस पहल का समर्थन किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक संरचना को अधिकतम पुनर्भरण दक्षता के लिए रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया था, फिर भी, प्रेरक शक्ति सामुदायिक नेतृत्व ही रहा। वैज्ञानिक योजना और जनभागीदारी के संगम ने एक स्थायी शासन मॉडल का निर्माण किया।

कोरिया मॉडल की मुख्य विशेषताएं

05 प्रतिशत मॉडल का सारः किसान अपनी जमीन के 05 प्रतिशत हिस्से में सोख्ता गड्ढे या छोटे तालाब बनाते हैं।

जल संरक्षण और उत्पादकताः वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर को रिचार्ज किया जाता है, जिससे मिट्टी की नमी बढ़ती है और कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।

सफलताः इस पहल से 440 से अधिक पारंपरिक तालाबों का पुनरूद्धार किया गया है।

राष्ट्रीय नीतिः इस मॉडल की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने इसे देशभर में लागू करने का निर्णय लिया है, जिस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में सहमति बनी।

05 प्रतिशत मॉडल ने पानी की कमी को किस प्रकार से जल सुरक्षा में बदल दियाः ऐसे समय में जब जल संकट सबसे गंभीर जलवायु चुनौतियों में से एक के रूप में उभर रहा है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे शक्तिशाली समाधान बड़े बांधों या भारी मशीनरी से प्रारंभ नहीं होते हैं, उनका शुभारंभ लोगों से होता है। जल संचय जन भागीदारी की भावना के माध्यम से जिले ने एक सरल लेकिन क्रांतिकारी प्रश्न पूछते हुए कि यदि प्रत्येक किसान स्वेच्छा से अपनी भूमि का केवल 5 प्रतिशत भाग जल संग्रहण के लिए समर्पित कर दे तो क्या होगा? आवा पानी झोकी आंदोलन के अंतर्गत, किसान स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा छोटे पुनर्भरण तालाबों और सीढ़ीदार गड्ढों के निर्माण के लिए अलग रखते हैं। ये संरचनाएं खेतों के भीतर ही वर्षा जल को एकत्रित करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मानसून की हर बूंद को संरक्षित, अवशोषित और पुनः उपयोग किया जा सके।

इसके परिणाम उल्लेखनीय रहे हैंः

- जो वर्षाजल पहले बह जाता था, अब वह मिट्टी और जलभंडारों को पुनर्भरण करता है।
- मृदा अपरदन में काफी कमी आई है
- सूखे के दौरान फसलों में नमी का स्तर बेहतर हुआ है।

मोदक एक स्थानीय समाधान है, जो स्वाद और सेहत दोनों को साथ लेकर चलता है। हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियों कुपोषण से मुक्तहो। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा लड्डू वितरण से पोषण स्तर

● भूजल पुनर्भरण स्थिर और निरंतर हो गया है।

यह मॉडल सिद्ध करता है कि सतत जल प्रबंधन के लिए व्यापक स्तर पर विस्थापन या भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। सामुदायिक एकता आंदोलन को गति प्रदान कर रही है। इस अभियान को व्यापक सामुदायिक भागीदारी से मजबूती मिली। महिलाएं नीर नायिका बनकर उभरीं, जिन्होंने घरों का मार्गदर्शन किया और जल संरक्षण के लिए गड्ढे बनवाने में अग्रणी भूमिका निभाई, साथ ही पारंपरिक लोकगीतों के माध्यम से जागरूकता फैलाई। युवा स्वयंसेवकों ने, जिन्हें जल दूत' के नाम से जाना जाता है, नालियों का मानचित्रण करके, नहरों से गाद निकालकर, नुक्कड़ नाटक के आयोजन और भित्ति चित्रों के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया और इस आंदोलन को उर्जा प्रदान की। सामूहिक श्रमदान से 440 से अधिक पारंपरिक तालाबों का पुनरुद्धार हुआ और वे प्राकृतिक जल पुनर्भरण के स्रोत बन गए। 05 प्रतिशत मॉडल की सफलता केवल बुनियादी ढांचे में ही नहीं, बल्कि स्वामित्व में भी निहित है। ग्राम सभा के प्रस्तावों के माध्यम से अपनाई गई और वैज्ञानिक योजना द्वारा समर्थित यह पहल वास्तव में एक जन आंदोलन बन गई। 1,260 से अधिक किसानों ने अपनी भूमि पर 5 प्रतिशत जल पुनर्भरण प्रणाली को अपनाया। संपूर्ण जिले में 2,000 से अधिक सोख गड्ढे बनाए गए। ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपने घरों के पास सोख गड्ढे बनवाए, जिससे जल पुनर्भरण दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया।

जल संचय जन भागीदारी का प्रभाव स्पष्ट और मात्रात्मक रूप से दिखाई दे रहा है:

● कई गांवों में भूजल स्तर 3 से 4 मीटर तक बढ़ गया है।

● 17 दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में झरने फिर से भर गए हैं।

● मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता बेहतर होने के कारण कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है।

● आजीविका स्थिर होने के कारण मौसमी प्रवास में अनुमानित 25 प्रतिशत की कमी आई है। जल सुरक्षा ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया है।

में सुधार स्पष्ट है। आने वाले समय में इसे और अधिक सघन तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे हर गर्भवती महिला इसका लाभ ले सके।निश्चित ही कोरिया मोदक केवल लड्डू नहीं, बल्कि पोषण, महिला सशक्तीकरण और भविष्य की पीढ़ी के

बिहान योजना और महतारी वंदन योजना से संवर रही ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बिहान योजना और महतारी वंदन योजना के तहत महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। रेडी-टू-ईट, वनोपज प्रसंस्करण और कोरिया मोदक (पोषण लड्डू) जैसे कार्यों से महिलाएं हर साल लाखों की कमाई कर लखपति दीदी बन रही हैं।

कोरिया में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख बिंदु:

कोरिया मोदक (पोषण लड्डू): आंगनबाड़ियों के लिए महिलाओं द्वारा निर्मित लड्डू से कुपोषण कम हो रहा है, और वे सालाना 1.5 लाख रूपये तक कमा रही हैं।

बिहान योजना: 4,000 स्व-सहायता समूहों में 40,000 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, जो साबुन, अगरबत्ती और कृषि-आधारित उत्पाद बना रही हैं।

महतारी वंदन योजना: राज्य सरकार द्वारा विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रूपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्तहो रही हैं।

रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ: स्व-सहायता समूहों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।

ई-रिक्शा से आत्मनिर्भरता: बिहान योजना के तहत ऋण लेकर महिलाएं ई-रिक्शा चलाकर आय के नए स्रोत बना रही हैं

ग्राम भट्ठीपारा और आसपास के इलाकों में महतारी वंदन योजना ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। राज्य सरकार द्वारा हर माह महिलाओं के बैंक खातों में एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता उनके परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने न केवल महिलाओं को सशक्त किया है, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है।

महिलाओं को मिल रहा है सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई महतारी वंदन योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक मजबूती दे रही है, बल्कि उन्हें समाज में नए अधिकार और सम्मान का एहसास करा रही है। इस योजना के तहत अब तक जिले की 59 हजार और प्रदेश की 70 लाख विवाहित महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। योजना ने महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और भविष्य की योजनाओं के स्वास्थ्य की गारंटी है। कोरिया जिले की यह पहल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय मॉडल बनने की ओर बढ़ रही है।

प्रति सजग भी बनाया है। यह योजना महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों और सशक्त भूमिका का एहसास कराने में अहम भूमिका निभा रही है। महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता और परिवारों को खुशहाली का मार्ग दिखाया है, जो समाज के विकास में नई मिसाल कायम कर रही।

बिहान कार्यक्रमः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित बिहान कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आज ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी बना रही हैं। जिले में भी बिहान से अनेक महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। बिहान से सशक्त हो रहीं ग्रामीण महिलाएं, स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी अलग पहचान बना रहीं। एक समय ऐसा था जब सीमित आय, आर्थिक असुरक्षा और स्थायी आजीविका के अभाव के कारण महिलाओं का जीवन संघर्षों से घिरा हुआ था। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संसाधनों की कमी के कारण जीवनयापन कठिन हो रहा था। ऐसे समय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह से जुड़ना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके भीतर आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की नई आशा जगाई। बिहान कार्यक्रम के तहत उरांव को समय-समय पर वित्तीय साक्षरता, समूह प्रबंधन, उद्यम विकास और आजीविका संवर्धन से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए। इन प्रशिक्षणों ने उन्हें केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि आत्मनिर्भर बनने, निर्णय लेने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का आत्मविश्वास भी प्रदान किया। जिला प्रशासन एवं एनआरएलएम के सहयोग से उनके स्व सहायता समूह को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत समूह को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि तथा बैंक ऋण की सुविधा प्राप्त हुई। इस वित्तीय सहयोग और प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया। वर्तमान में वे कपड़ों के व्यापार सहित का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। उनके निरंतर परिश्रम, सही मार्गदर्शन और समय पर मिली वित्तीय सहायता का परिणाम है कि आज उनकी वार्षिक आय लगभग 08 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ-साथ सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि हुई है। आज वो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी हैं। वे अपने गांव की अन्य महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जुड़ने, बचत की आदत अपनाने और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में उभरा कोरिया जिला

कोरिया, छत्तीसगढ़ का उत्तर-पश्चिमी जिला, अपने घने जंगलों, झरनों (जैसे गौरघाट), पहाड़ों और ऐतिहासिक स्थलों के दम पर एक प्रमुख ईको-टूरिज्म हब के रूप

लखपति दीदी अभियान से छत्तीसगढ़ की महिलाएं लिख रही समृद्धि की नई कहानी: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के बल पर नई पहचान बना रही हैं और हमारी सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्तबनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है और जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का निवास होता है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं घरों तक सीमित रहती थीं, लेकिन आज प्रदेश की महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्तहो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन का लक्ष्य लखपति दीदियों को और अधिक सशक्त बनाकर गांव की प्रत्येक महिला को लखपति बनाना और भविष्य में लखपति ग्राम का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 10 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के लोगों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है और इनके निर्माण में बिहान की दीदियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को 24 किश्तों में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है तथा इस वर्ष के बजट में इसके लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लखपति दीदी योजना से प्रदेश की 05 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।

मातृ पोषण को मिला नया आधार: इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के पांचवें माह से लेकर प्रसव तक गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दो पौष्टिक कोरिया मोदक लड्डू दिए जाते हैं। इन लड्डुओं को मौसम और उपलब्धता के आधार पर रागी, सत्तू, गुड़, मूंगफली, तिल, चना, जौ और घी जैसी पौष्टिक सामग्री से तैयार किया जाता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से तैयार यह लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आयरन, प्रोटीन और उर्जा का समृद्ध स्रोत बन गया है।

में तेजी से उभर रहा है। बैकुंठपुर के झुमका बोट क्लब, कोरिया पैलेस और गुरूघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। स्थानीय संस्कृति, लजीज व्यंजनों और होमस्टे के जरिए यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा

समन्वय व संवेदनशीलता: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पोषण संगवारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला को नियमित रूप से इन लड्डुओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही घर-घर जाकर महिलाओं को इनके सेवन के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, जिससे मातृ पोषण के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है।

सकारात्मक परिणामों ने बढ़ाया भरोसा: कोरिया मोदक पहल के प्रभाव से जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। इस पहल के परिणामस्वरूप कम जन्म वजन वाले शिशुओं के मामलों में लगभग 57 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं 95.9 प्रतिशत नवजात शिशुओं का जन्म वजन 2.5 किलोग्राम से अधिक पाया गया है, जो बेहतर मातृ पोषण का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रारंभिक एएनसी पंजीयन और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया गया है। वहीं 90 प्रतिशत से अधिक कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं में संतोषजनक वजन वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि यदि स्थानीय स्तर पर सही रणनीति और सामुदायिक भागीदारी के साथ प्रयास किए जाएं, तो कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से प्रभावी तरीके से मुकाबला किया जा सकता है।

महिलाओं को मिला आर्थिक सशक्तीकरण: इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण का अवसर मिला है। ज्योति और माँ शारदा स्व-सहायता समूह की लगभग 22 महिलाएं प्रतिदिन 5,000 से 6,000 कोरिया मोदक लड्डू तैयार कर रही हैं। अब तक 18 लाख से अधिक लड्डू वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्य से प्रत्येक महिला को प्रतिमाह लगभग 10 से 12 हजार रूपये की आय हो रही है। यानी एक वर्ष में उन्हें एक से डेढ़ लाख रूपये तक की आय प्राप्त हो रही है। इससे महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ-साथ सम्मानजनक आजीविका का अवसर भी मिला है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान: कोरिया मोदक पहल की सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। इस अभिनव मॉडल की प्रशंसा नीति आयोग ने भी की है। आयरन और प्रोटीन से भरपूर ये लड्डू गर्भवती महिलाओं में एनीमिया कम करने और नवजात शिशुओं के कम वजन की समस्या को दूर करने में प्रभावी साबित हो रहे हैं। इस पहल को नीति आयोग की स्पेरियेशनल टाइम्स न्यूज़लेटर में स्थान मिला है और इसे आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत एक स्केलेबल बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में भी सराहा गया है।

है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित कोरिया अपने मनोरम दृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस जिले का एक प्रमुख आकर्षण गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक विशाल अभयारण्य है और वन्यजीव प्रेमियों

जैविक खेती से ग्रामीण महिलाओं ने बदली तकदीर, बन रहीं आत्मनिर्भर

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के छोटे से गांव केशगंवा की 20 महिलाएं आज जैविक खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। ये महिलाएं, जो कभी घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, अब अपने खेतों में लौकी, करेला, मिर्ची और टमाटर जैसी सब्जियों की जैविक खेती कर न केवल अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। स्व-सहायता समूहों के जरिए इन महिलाओं ने उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 50-50 डिसमिल जमीन पर लौकी और करेला, साथ ही एक-एक एकड़ में मिर्ची और टमाटर की खेती शुरू की है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्तये फसलें पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के साथ-साथ स्वाद और पोषण में भी बेहतर हैं।

मेहनत का फल, खेत से बाजार तक: इन महिलाओं की मेहनत अब रंग ला रही है। वे अपनी फसलें स्थानीय थोक मंडियों और फुटकर विक्रेताओं को बेचकर नियमित आय कमा रही हैं। अब तक उन्होंने 15-15 क्विंटल लौकी और करेला बेचा है, जिससे 35 हजार रुपये की कमाई हुई है। एक महिला किसान ने बताया, पहले हम सिर्फ घर संभालते थे, लेकिन अब खेत हमारी ताकत बन गए हैं। हमारी फसलें गांव की हर रसोई तक पहुंच रही हैं।

जैविक खेती को मिला सहारा: इन स्व-सहायता समूहों को 1690 हाइब्रिड पौधों के साथ-साथ फेंसिंग, मल्चिंग, ड्रिप सिस्टम, जैविक खाद और दवाइयां मुहैया कराई गई हैं। इस पहल ने न सिर्फ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।

पर्यावरण और आजीविका का संगम: यह पहल सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। जैविक खेती के जरिए ये महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही हैं। बिना रासायनिक खाद के उगाई गई सब्जियां न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं। एक महिला किसान ने गर्व से कहा, अब हम खुद को किसान कहती हैं। हमारी मेहनत से न सिर्फ हमारा घर चल रहा है, बल्कि गांव का नाम भी रोशन हो रहा है।

चुनौतियां और उम्मीदें: हालांकि, जैविक खेती का रास्ता आसान नहीं है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, लेकिन उचित दाम और नियमित खरीदार ढूंढना अभी भी चुनौती बना हुआ है। फिर भी, इन महिलाओं का हौसला कम नहीं हुआ है। वे उम्मीद करती हैं कि भविष्य में और अधिक संसाधन और प्रशिक्षण मिलने से उनकी कमाई और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव की ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि मेहनत और सही दिशा मिले तो कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। उनकी यह कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि ग्रामीण भारत के बदलते चेहरे की झलक भी दिखाती है।

को इस क्षेत्र की जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय उद्यान तेंदुओं, चीतल और जंगली सूअरों सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल बनाता है। इस क्षेत्र

छत्तीसगढ़ का ये कैसा लजीज अचार? महिलाओं ने 03 महीने में कमा डाले 03 लाख रूपये

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की मिट्टी में बसे स्वाद और परंपरा ने अब देशभर में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। जहां पहले गांवों की महिलाएं घर तक सीमित रहती थीं, वहीं अब वे अपने हुनर से न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वाद को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रही हैं। कोरिया जिले की नीलम कुशवाहा और उनके महिला समूह की कहानी इसी बदलाव की मिसाल है। नीलम बताती हैं कि वह एक महिला समूह से जुड़ी हुई हैं, जहां 08 से 10 महिलाएं मिलकर घर में बने शुद्ध और पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए 09 से 10 तरह के अचार बनाती हैं। इस समूह की खासियत यह है कि यहां बनने वाला अचार पूरी तरह लोकल तरीके से और लोकल चीजों से तैयार किया जाता है। नीलम कहती हैं, कोरिया का अचार मतलब गांव का अचार। यह पूरी तरह देसी, बिना मिलावट और परंपरा से भरपूर अचार है। महिलाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले अचार में आंवला, कटहल, आम, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और करौंदे का अचार शामिल है। हर अचार को महिलाएं पूरी शुद्धता और साफ-सफाई के साथ तैयार करती हैं। यह केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि कोरिया जिले की मेहनतकश महिलाओं की पहचान बन चुका है। नीलम कुशवाहा बताती हैं कि इन अचार की कीमत उनके वजन के अनुसार तय की गई है। 250 ग्राम आम का अचार 100 रूपये, 200 ग्राम लहसुन का अचार 80 रूपये, 250 ग्राम नींबू और करौंदा अचार 100 रूपये जबकि कटहल का अचार भी 100 रूपये में डिब्बे में उपलब्ध है। इन उत्पादों की बिक्री लोकल मार्केट, कलेक्टोरेट परिसर और आसपास के इलाकों में की जाती है, जहां ग्राहकों को देसी स्वाद की तलाश होती है। हाल ही में महिला समूह दिल्ली में आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी में शामिल हुआ। नीलम कुशवाहा बताती हैं कि दिल्ली में लोगों ने जब पहली बार कोरिया का अचार चखा, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो घर का असली स्वाद है। ऐसा अचार हमने पहले कभी नहीं खाया। दिल्ली में उनकी टीम ने 80 हजार रुपये का अचार बेचा था, जो समूह के लिए बड़ी बात है।

आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी छलांग: महिला समूह की यह पहल न सिर्फ आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम है बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की भी प्रतीक है। केवल तीन महीनों में ही इन महिलाओं ने तीन लाख रूपये से ज्यादा की आय अर्जित की है। नीलम कहती हैं कि पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गांव में बना अचार दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बिकेगा। अब हमें गर्व है कि हमारे अचार के स्वाद से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है।

में कई प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी हैं जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इनमें से गौराघाट जलप्रपात एक बेहद खूबसूरत नजारा पेश करता है। घने जंगलों के बीच स्थित यह जलप्रपात ताजगी भरी छुट्टी बिताने के लिए एकदम सही जगह है और

राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान की कोशिश

हमारा प्रयास है कि जिले में शासकीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। यहां के निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश स्तर पर मंच प्रदान किया जा रहा है ताकि वह पारंपरिक व्यवसायों के प्रोडक्ट को पहचान मिल सके। वहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से शासकीय मदद प्रदान की जा रही हैं। जिससे उनके व्यवसाय बढ़ रहे हैं। शासकीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों से जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो रहा है। आज कोरिया जिला अपनी पहचान खुद बना पा रहा है।

-डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, सीईओ, जिला पंचायत, कोरिया

शासकीय योजनाओं से लाभांवित हो रहे लोग

एक समय था जब कोरिया जिले को पिछड़ा और गरीब जिला माना जाता था। यहां के लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते थे। क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया है। लोग स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पहचान बना रहे हैं। जैविक शहद सोनहनी, कोरिया मोदक, बिहान योजना और महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं। अच्छी खासी कमाई कर परिवार के हाथ बंटा रही हैं। सरकार के सहयोग से संचालित इन योजनाओं से लोग लाभांवित हो रहे हैं।

-विजय मानिकपुरी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, कोरिया

पिकनिक व विश्राम के लिए शांत वातावरण प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित एक अन्य लोकप्रिय जलप्रपात अंकुरी नाला जलप्रपात है, जो अपने प्रखर प्रवाह और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये जलप्रपात उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो एक साथ शांति और रोमांच की तलाश में हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, कोरिया में कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें प्राचीन मंदिर और गुफाएं शामिल हैं जो स्थानीय विरासत की झलक पेश करते हैं। इस जिले में वन्यजीवों, झरनों और शांत परिदृश्यों का अनूठा मिश्रण इसे तेजी से

प्रदेश का मुखिया वही जो समस्याओं का करें समाधान- श्रीमती कविता

आज की भागमभाग भरी जिंदगी में, हर एक पैसे की कीमत क्या होती है, यह वही समझ सकता है जिसने आभाव और मजबूरी में जीवन व्यतीत किया है। हमारे समाज और परिवार में एक-एक पैसे की कीमत कामकाजी महिलाएं और गृहणियां बेहतर समझती हैं। घर-परिवार में गृहणियों को सब्जी, राशन, दवाई, शिक्षा, मेहमान नवाजी से लेकर भविष्य की चिंता करते देखा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वन्दन योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी है। महतारी वन्दन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को हर माह राज्य शासन द्वारा एक हजार रुपए उनके खाते में अंतरित की जाती है ताकि अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

कोरिया जिले में योजना का क्रियान्वयनः छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिला कोरिया में भी इस योजना का सफल क्रियान्वयन हुआ है। ग्राम उपर पारा, खरवत में रहने वाली श्रीमती कविता पति विमल कुमार, जो आठवीं तक पढ़ी हैं और तीन बच्चों की मां हैं, इस योजना का लाभ उठाने वालों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक उनके खाते में चार किस्त की राशि आ चुकी है। श्रीमती कविता ने कहा कि इस योजना के फार्म भरते समय उन्हें पूरा भरोसा था कि यह राशि उन्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस राशि से उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी-पेन खरीदे और घर के लिए राशन व सब्जी भी खरीदी कर रही है।

महिलाओं के जीवन में परिवर्तनः श्रीमती कविता ने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो सबकी चिंता दूर करें, परेशानियों से निजात दिलाए वही देश, प्रदेश और घर का मुखिया होता है। श्रीमती कविता ने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना से वे और उनका परिवार बहुत खुश हैं। निश्चित ही महतारी वन्दन योजना ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उनके जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी बढ़ाई है। इस योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता ने महिलाओं को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार की यह पहल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना रहा है।

गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अमृतधारा, गौरघाट जलप्रपात, कुबेरघाट, समुन्दइ, नीलकण्ठ दसेर, बदरा भित्तिचित्र, रमदहा जलप्रपात, देवगढ़ की पहाड़ियां, चांग माता का

कोरिया बना स्वास्थ्य सुरक्षा का मॉडल

देशभर में गरीब व जरूरतमंदों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाकर 05 लाख रु पए तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लगातार गरीब व जरूरतमंद तबकों के बेहतर इलाज के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जिले में 94.6 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि 106.3 प्रतिशत परिवार इस योजना के तहत कवर हो चुके हैं। कोरिया जिले में 2.76 लाख राशन कार्डधारी परिवारों में से 2.61 लाख को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा, जिले के 45 ग्राम पंचायतों (134 गांवों) में 95 प्रतिशत से अधिक कवरेज पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की नियमित समीक्षा बैठक और गांव-गांव लगाए गए शिविरों ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने अभियान की अगुवाई करते हुए सुनिश्चित किया कि हर पात्र व्यक्तिको इस योजना का लाभ मिले। इसके अलावा आरोग्य मिशन के तहत निकुष्ट उन्मूलन अभियान भी चलाया जा रहा है। कोरिया जिला स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में नई उंचाइयों को छू रहा है। इस उपलब्धि ने कोरिया को प्रदेश भर में स्वास्थ्य योजना क्रियान्वयन का मॉडल जिला बना दिया है और इस तरह पूरे प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है।

मंदिर, कोरिया पैलेस, जगन्नाथ मंदिर, गांगी रानी मंदिर, शिवधारा जलप्रपात जटाशंकर, सिद्धबाबा धाम ,हसदेव तट, महामाया मंदिर, कर्क रेखा और क्ष्च्र मेरिडियन का संगम स्थल सोनहत इत्यादि यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है।

जिले में नदियों, पहाड़ों और घने जंगलों की भरमार है, जो इसे एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं। गौरघाट जलप्रपात (हसदेव नदी पर), बानीयाधारा झरना और अन्य छोटे-बड़े झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बैकुंठपुर के पास स्थित, यह एक प्रमुख आकर्षण है, जहाँ बोटिंग की सुविधा के साथ अब ओपन थिएटर भी विकसित किया जा रहा है। गुरूघासीदास टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। स्थानीय प्रशासन

जिले में नदियों, पहाड़ों और घने जंगलों की भरमार है, जो इसे एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं।

होमस्टे और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें कोदो-कुटकी के व्यंजन और स्थानीय कला को भी शामिल किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स की मदद ली जा रही है। कोरिया का यह अनूठा संगम, जहाँ इतिहास और प्रकृति का मेल है, इसे राज्य में पर्यटन के लिए एक नई पहचान दे रहा है।

कोरिया विविधाताओं से भरपूर है। वर्षा ऋतु में जब प्रकृति अपने सौन्दर्य की चरम सीमा पर होती है तो ये कोरिया जिले की कुछ महत्वपूर्ण नदियों पर बनने वाली

कोरिया विविधाताओं से भरपूर है। वर्षा ऋतु में जब प्रकृति अपने सौन्दर्य की चरम सीमा पर होती है तो ये कोरिया जिले की कुछ महत्वपूर्ण नदियों पर बनने वाली जलप्रपात को भी सुन्दरता प्रदान करती है ये जलप्रपात स्वतः ही अपनी सुन्दरता बिखेरती है पूर्णता प्राकृतिक रूप से बनी ये जल प्रपात आस पास के लोगो आकर्षित करती है

जलप्रपात को भी सुन्दरता प्रदान करती है ये जलप्रपात स्वतः ही अपनी सुन्दरता बिखेरती है पूर्णता प्राकृतिक रूप से बनी ये जल प्रपात आस पास के लोगो आकर्षित करती है इस जिले में ऐसे कई जल प्रपात है जैसे गौरघाट, बनियाधारा नदी एवं जलप्रपात। इसके अतिरिक्त झुमका बोट क्लब जो कि जिला मुख्यालय में स्थित है, को जिला प्रशासन की मदद से पर्यटनीय क्षेत्र रूप में बनाया गया है। ब्लॉक मुख्यालय सोनहत से पोडी होकर रजौली मार्ग पर 04 कि.मी. की दूरी पर ग्राम अमहर के घुनघुटा नदी में लगभग 30 से 40 मीटर लंबी एवं 30 से 40 फुट उंची दिवार बनाकर एक वृहद क्षेत्र में घुनघुटा बांध का निर्माण किया

गया है। घुनघुटा बाध के पश्चिम दक्षिण भाग में पहाड़ियों से घिरे मैदानी भाग पर बने रिसार्ट की छवि अदभूत है, यहां 3 ट्री हाउस एक काफीटेरिया तथा एक घास का मैदान का निर्माण हुआ है। पर्यटकों को चाँदनी रात में इन स्थानों पर रूकने से जंगली जानवरों को देखने, चांदनी रात में घुनघुटा बांध के जल किरणों की अटखेलिया देखने का मनोहारी अनुभव है। यहां पर फिशोंग, सायकिलिंग एवं ट्रेकिंग भी की जा सकती है।

कोरिया के प्रमुख पर्यटन स्थल

झुमका बांध

कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के रेलवे स्टेशन से 05 किलोमीटर दूर पर झुमका बांध है। ये बांध एकदम समुद्र की तरह दिखता है. जहां तक नजर जाए वहां तक पानी ही नजर आता हैप्र इस बांध का निर्माण 1982 में हुआ था। इसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने किया था। इसे रामानुज प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। झुमका बांध पर्यटकों के लिए खास जगह तो है ही। इसके अलावा यह बांध किसानों के लिए भी काफी उपयोगी है। झुमका बांध से लगभग 1100 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। इससे 17 गांव के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। झुमका बांध किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा यह कोरिया जिले सहित सरगुजा संभाग के लोगों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां पर्यटकों के लिए बैठने की, बोटिंग और फिशिंग की सुविधाएं हैं। रूकने के लिए रिजार्ट भी बना हुआ है। बांध के आसपास काफी खूबसूरत प्राकृतिक नजारा है। पेड़-पौधे सहित अलग तरह से पत्थरों का समूह भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस बांध में घूमने के लिए हर मौसम उपयुक्त है। क्योंकि यहां सालभर पानी भरा रहता है। बारिश के मौसम में अधिक पानी भरा होने की वजह से और भी सुंदर नजारा देखने को मिलता है। झुमका बांध लोगों की पसंदीदा जगहों में इसलिए भी खास है क्योंकि यहां बहुत बड़ा कृत्रिम मछली बना हुआ है। जिसके अंदर फिश एक्वेरियम है।

गौरघाट जलप्रपात

हसदेव नदी पर स्थित यह झरना जो कोरिया के जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। 60 फीट की उंचाई से गिरता पानी और आस-पास की हरियाली देखने यहां दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस वॉटरफॉल के जल कुंड में गौर पशु आराम किया करते थे, इसी वजह से इसका नाम गौरघाट पड़ा। जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर से नगर ग्राम होकर बसेर पहुंचकर इस स्थल पर पहुंचा जा सकता है एवं सोनहत मुख्य मार्ग के कटगोडी ग्राम से पश्चिम दिशा की ओर दामुज बसेर होकर जाया जा सकता है। यहां हसदो नदी पर बनने वाले पहले जल

प्रपात को गौरघाट जलप्रपात कहा जाता है। प्रपात के गिरने के स्थल के पहले एवं प्रवाह की ओर अकॅत प्राकृतिक सौदर्यता प्रकृत ने स्थापित कर रखी है जो पर्यटकों को बारम्बार यहां आने हेतु आमंत्रित करती है।

गुरुघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व

छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित है।

यह 2,829 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे भारत में तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बनाता है। कोरिया जिले इसकी भगौलिक सीमा उत्तर में आनन्दपुर से दक्षिण में मेंन्ड्रा, पूर्व में जोगिया, सुखतरा से पश्चिम में गरनई- चंदहा तथा विस्तृत वन भाग 1440.70 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिनमें कई हिल स्टेशन, बालंद गढ़ी भादा पहाडिया, खेखरा कोड़ा माझीगढ़ भैरवगढ, गढ पहाडी रेवला आदि चाटिया है। गोपद, हसदो, बनास, पैरी, बीजाधुर, बनिया आदि नदियां, झरनों का उद्गम स्थल एवं प्रवाह तंत्र इस राष्ट्रीय उद्यान के भू-भाग में समाहित है। वनस्पतियों के अकूत भण्डार यहां अपने औषधी के तेजराज, भोजराज, भृगराज, पथरनीम, शेरचारा, आवाला, हर्रा, बहेरा के रूप में है। राष्ट्रीय पशु बाघ तेदुआ हाथी बंदर, चिंगारा, कोटरी, भेडिया, उदबिलाव, चीतल आदि जानवर दिखाई पड़ते हैं। पंक्षियों के लिए यह एक सुरक्षित स्थान है। पक्षियों में वन मुर्गा, मोर, धनेश, बाज, चील, हुदहुद, किगफिशर, मैना, बगुला आदि पक्षी पाए जाते हैं। वन में साल, हल्दू, तेदु, चार, सीधा, आवला, कुसुम, साजा, जामुन, बरगद आदि के वृक्ष बहुतायत में है। यह रिजर्व रणनीतिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण रिजर्वों से जुड़ा हुआ है, जिसमें उत्तर में मध्य प्रदेश में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पश्चिम में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पूर्व में झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व शामिल हैं। यह परस्पर जुड़ा नेटवर्क लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर का परिदृश्य परिसर बनाता है जो प्रभावी संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देता।

जलप्रपात

अमृतधारा जलप्रपातः हसदेव नदी पर स्थित, यह सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है।

रामदहा जलप्रपातः बनास नदी पर स्थित, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोकप्रिय है।

गौरघाट जलप्रपातः हसदेव नदी पर, बैकुंठपुर से 35 किमी की दूरी पर स्थित है।

अकुरी नालाः यह भी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थल है।

झुमका बांध (झुमका आईलैंड): बैकुंठपुर के पास स्थित, यह एक बड़ा जलाशय है जहाँ बोटिंग और रिसॉर्ट की सुविधा उपलब्ध है।

अमहार रिसार्ट (घुनघुट्टा बांध): सोनहाट के पास एक मनोरम स्थल है।

बनियाधारा नदी-जलप्रपातः सोनहाट में स्थित एक सुंदर पर्यटन स्थल।

बलम गाड़ीः एक साहसिक और प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र।

वन्यजीव और धार्मिक स्थलः

गुरूघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्वः यह क्षेत्र जैव विविधता से भरा है।

जोगीमठ और देवधामः पुराने और धार्मिक स्थलों में शामिल हैं।

महतारी वंदन योजना :

आर्थिक संबल से आत्मविश्वास तक, सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की महिलाएं

डॉ. दानेश्वरी संभाकर,
उप संचालक जनसंपर्क

किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब मानी जाती है जब उसकी महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने लगें। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में यह योजना आज लाखों महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, आर्थिक संबल और नई उम्मीदों का संचार कर रही है।

महतारी वंदन योजना केवल हर माह मिलने वाली 1000 रु पये की आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सपनों को पंख देने, उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन गई है। प्रदेश के गांव-गांव से ऐसी प्रेरक कहानियां सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि छोटे-छोटे आर्थिक सहयोग से भी बड़े सामाजिक बदलाव संभव हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में यह योजना आज लाखों महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, आर्थिक संबल और नई उम्मीदों का संचार कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर में आयोजित वृहद महतारी वंदन कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से वर्चुअल संवाद कर अपने जीवन में आए बदलाव साझा किए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम खोडरी की श्रीमती अनीता साहू ने बताया कि पहले आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिवार चलाना मुश्किल था, लेकिन योजना से मिली राशि से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और अनीता सिलाई सेंटर शुरू किया। आज वे सिलाई, खेती और मजदूरी के माध्यम से अपने परिवार को बेहतर

जीवन दे रही हैं। उनका यह सफर संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक कहानी बन गया है।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की श्रीमती मिथलेश चतुर्वेदी ने भी अपने जीवन का भावुक अनुभव साझा किया। पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। ऐसे कठिन समय में महतारी वंदन योजना ने उन्हें आर्थिक संबल दिया और उन्होंने ई-रिक्शा खरीदकर आजीविका का नया रास्ता चुना। आज वे आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं और समाज में आत्मनिर्भर महिला की पहचान बना चुकी हैं।

कोरिया जिले की ग्राम डुमरिया निवासी श्रीमती बाबी राजवाड़े बताती हैं कि खेती-किसानी में मिलने वाली मासिक राशि उनके लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। वहीं ग्राम आमापारा की श्रीमती सुंदरी पैकरा इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई में कर रही हैं, जिससे उनके बच्चों के भविष्य को नई दिशा मिल रही है।

भरतपुर विकासखंड के ग्राम चांटी की श्रीमती सविता सिंह की कहानी इस योजना की सार्थकता को और मजबूत करती है। उन्होंने महतारी वंदन योजना की राशि को बचाकर सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई कार्य शुरूकिया। आज वे गांव में कपड़ों की सिलाई कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च स्वयं उठा रही हैं। उनकी सफलता ने गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है।

महतारी वंदन योजना का व्यापक प्रभाव प्रदेश के हर जिले में दिखाई दे रहा है। लगभग 69 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रु पये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है और अब तक 25 किस्तों के माध्यम से 16 हजार 237 करोड़ रु पये से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए प्रदान की जा चुकी है। यह नियमित आर्थिक सहयोग महिलाओं के जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास ला रहा है।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महिलाओं को केवल सहायता नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। महिलाएं इस राशि से छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई में निवेश कर रही हैं, खेती-किसानी को मजबूत बना रही हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे परिवार, समाज और राज्य तीनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।

महिलाओं का कहना है कि पहले छोटी-छोटी जरू रतों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब महतारी वंदन योजना ने उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्तकरते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास लेकर आई है।

आस्था का दिव्य महाकुंभ

पूरा विश्व देखेगा उज्जैन का वैभव

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

30 करोड़ श्रद्धालुओं का स्वागत
उज्जैन नगरी का हो रहा अभूतपूर्व कायाकल्प

सुगम आवागमन ₹ 13,536 करोड़ से 581 कि.मी. मार्गों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत

पुल निर्माण ₹440 करोड़ के निर्माण से यातायात का बेहतर प्रबंधन

शुद्ध जल क्षिप्रा के लिये ₹ 919 करोड़ लागत की कान्ह क्लोज्ड डक्ट परियोजना एवं शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु ₹1113 करोड़ के कार्य जारी

घाट निर्माण लगभग 29 कि.मी. घाटों का निर्माण जारी

ज़ीरो वेस्ट इवेंट जन भागीदारी से ज़ीरो वेस्ट इवेंट बनाने की पहल

मंदिरों का जीर्णोद्धार
सभी पौराणिक मंदिर जैसे हरसिद्धि, गढ़कालिका का विकास

आधुनिक तकनीक से प्रबंधन
भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रांसपोर्ट और कंट्रोल रूम तक एआई का उपयोग

कनेक्टिविटी विश्वस्तरीय उज्जैन हवाई अड्डा और सदावल में 4 हेलीपैड का निर्माण कार्य जारी

उज्जैन बनेगा मेडिकल हब
₹ 592.30 करोड़ लागत से मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन

"सिंहस्थ महापर्व 2028 करोड़ों भक्तों को सरल, सुलभ और नवीनतम सुविधाओं से युक्त विश्व-स्तरीय कुंभ का अनुभव प्रदान करना हमारा संकल्प है।"

- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

R.O. No. D19006/26

महिलाएं सशक्त प्रगति का मार्ग प्रशस्त

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण एक नए मिशन में बदल गया है, जहां प्रदेश की हर महिला प्रगति के पथ पर एक स्वावलंबी भागीदार है।

मध्यप्रदेश के प्रगतिशील परिवर्तन की स्वावलंबी भागीदार नारी शक्ति

सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

- 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को हर माह ₹1500 की सहायता से सुनिश्चित हो रहा **आर्थिक स्वावलंबन**
- महिलाओं के नाम संपत्ति पर रजिस्ट्री शुल्क में 2% विशेष रियायत से मिला भूमि और संपत्ति पर अधिकार
- 62 लाख **महिलाएं स्व-सहायता** समूहों से जुड़कर हुईं आत्मनिर्भर
- **'लखपति दीदी योजना'** से 12 लाख+ महिलाओं की वार्षिक आय हुई ₹1 लाख से अधिक
- 89 लाख महिलाओं को **उज्ज्वला** गैस कनेक्शन और लाड़ली बहनों को **₹450 में सस्ते गैस सिलेंडर से मिली** रसोई में राहत
- 'एक बगिया माँ के नाम' अभियान से कृषि में बढ़ रही भागीदारी

प्रशासनिक-राजनीतिक भागीदारी

- शासकीय नौकरियों में **35% तक आरक्षण** से बढ़ी प्रशासनिक एवं निर्णयकारी पदों पर महिलाओं की मौजूदगी
- पंचायत एवं नगरीय निकायों में **50% तक आरक्षण से मिली लोकतंत्र** में ऐतिहासिक भागीदारी

सुरक्षा ने बढ़ाया आत्मविश्वास

- **'वन स्टॉप सेंटर'** से हिंसा पीड़िता को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य और कानूनी परामर्श, हर जिले में सुरक्षित एवं त्वरित सहायता
- थानों में विशेष **महिला हेल्प डेस्क**
- संकट की स्थिति में डायल **181/ 1098** या **112** पर तुरंत सहायता
- छात्राओं एवं कार्यरत महिलाओं के लिए **सुरक्षित और किफायती छात्रावास**

शिक्षा एवं रोज़गार के अवसरों तक पहुंच

- जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता दे रही **लाड़ली लक्ष्मी योजना**
- जन्मदर सुधार, शिक्षा प्रोत्साहन और बालिकाओं की सुरक्षा पर केंद्रित अभियान **बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ**
- **एमएसएमई** इकाइयों में महिलाओं को प्रोत्साहन, 47% से अधिक एमएसएमई महिलाओं के नेतृत्व में संचालित
  - कौशल, परामर्श और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु **हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन** एकीकृत केंद्र संचालित
  - कौशल और रोज़गार सहायता के लिए **'हम होंगे कामयाब' कार्यक्रम**

स्वास्थ्य की बेहतरी

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** से गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण सहायता
- **जननी सुरक्षा योजना** से ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को सीधी सहायता
- गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए पोषण तथा बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा हेतु **आंगनवाड़ी सेवाएं**
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में जागरूकता हेतु **सुमन सखी चैटबॉट** की शुरुआत

डॉ. मोहन यादव अभ्युदय मध्यप्रदेश

R.O. No. D19006/26

युद्ध का नया हथियार डिजिटल गड़बड़ी

प्रमोद भार्गव

संचार क्रांति से हमें वैश्विक वार्तालाप एवं समुद्र तथा आसमान में मार्गदर्शक सुविधाएं प्राप्त हैं। किंतु अब यही सुविधाएं होर्मुज जलडमरू मध्य के संकीर्ण मार्ग में जहाजों के भटकाव का आधार बन रही हैं। जिस जीपीएस प्रणाली से चालक दल अपना समुद्री मार्ग निर्धारित करते हैं, उसमें अब इलेक्ट्रोनिक गड़बड़ी पैदा करके जहाजों को भटकाया जा रहा है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे घमासान में समुद्र और आसमान के बीच नेविगेशन अर्थात सही मार्ग से भटकाव का संकट पैदा कर दिया है। युद्ध में सेनाएं और तकनीकी विषेशज्ञ जीपीएस-जैमिंग (रेडियो सिग्नल) और स्पूफिंग (छद्म पहचान) का सहारा लेती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा के सामने ये मार्गदर्शक तकनीक बधाएं खड़ी कर रही हैं। इसके चलते सागर में गतिमान व्यापारिक जहाज अपनी वास्तविक स्थिति से एक तो अलग-थलग दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तय मार्ग से भटक भी रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में यह जोखिम इसलिए गंभीर हो जाता है, क्योंकि गलत दिशा में गया जहाज सीधे टकराव, उथले पानी या हमले की जद में आ जाता है।

जार्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की साइबर सुरक्षा शोधकर्ता अन्ना रेमेकर

के अनुसार आधुनिक जहाजरानी उपग्रह आधारित जीपीएस पर अत्याधिक निर्भर है। यह प्रणाली पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों से आने वाले संकेतों के आधार पर मानचित्र में जहाज की स्थिति निष्चित जगह बताती है। रिसीवर इन रेडियो संकेतो के पहुंचने में लगने वाले समय की गणना करके स्थल निर्धारित करता है। चूंकि समुद्र की सतह या धरती पर पहुंचते-पहुंचते ये संकेत अत्यंत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए इनमें हस्तक्षेप करना सरल होता है। जीपीएस संबंधी बधाएं दो तरीकों से डाली जाती हैं, एक जैमिंग और दूसरी स्पूफिंग। जैमिंग में हमलावर विद्युत-चुबंकीय शोर पैदा करके असली उपग्रह संकेतों को भ्रामक बना देते हैं। इस कारण रिसीवर या चालक संकेत समझ नहीं पाने के कारण भटक जाते है। ऐसी स्थिति में नेविगेशन स्क्रीन स्थिर हो सकती है या अचानक गलत दिशा दिखाने लगती है। जीपीएस जैमिंग में व्यवधान पैदा करने की दृष्टि से सेनाएं उसी फ्रीक्वेंसी पर हाई-इंटेसिटी रेडियो सिग्नल भेजती हैं, जिसका उपयोग जीपीएस सिस्टम करता है।

स्पूफिंग एक ऐसी जटिल तकनीक है, जो असली पहचान छिपाकर छल-कपट करने में दक्ष होती है। इसमें उपग्रह से भेजे जाने वाले नकली संकेत इस प्रकार भेजे जाते है कि जहाज का रिसीवर उन्हें अस्ली समझ लेता है। यह संकेत 20000 किमी

स्पूफिंग एक ऐसी जटिल तकनीक है, जो असली पहचान छिपाकर छल-कपट करने में दक्ष होती है। इसमें उपग्रह से भेजे जाने वाले नकली संकेत इस प्रकार भेजे जाते है कि जहाज का रिसीवर उन्हें अस्ली समझ लेता है।

की दूरी तय करके सतह पर आते है। परिणामस्वरूप जहाज की लोकेशन गलत दिखाई देने लगती है। यदि जहाज उत्तर दिशा में जा रहा हो तो जीपीएस प्रणाली उसे दक्षिण दिशा में जाना दिखाने लगती है। खुले एवं सपाट समुद्र में इस गड़बड़ी की असली पहचान बेहद कठिन हो जाती है। ऐसी स्थिति में जलडमरू मध्य जैसे संकीर्ण मार्गों में यह स्थिति खतरनाक बन जाती है, क्योंकि तब गलियारा सकरा होने के कारण शत्रु द्वारा किसी जहाज को निषाना बनाना आसान हो जाता है। होर्मुज जैसे संकरे समुद्री मार्ग में संकट इसलिए अधिक हो जाता है, क्योंकि यहां जल की गहराई तीव्रता से बदलती रहती है और जहाजों के पास दिषा सुधारने के लिए बहुत कम समय होता है। तेल और गैस जैसे बड़े मालवाहक जहाज अत्यंत धीमी गति से मुड़ते हैं, इसलिए मामूली गलती भी टकराव या हमले का कारण बन जाती है। होर्मुज क्षेत्र को वैश्विक उर्जा आपूर्ति और व्यापार का

सबसे अधिक संवेदनशील केंद्र माना जाता है। दुनिया का 20 प्रतिशत उर्जा व्यापार इसी मार्ग से होता है। कतर जैसे देशों से होने वाली तरल प्राकृतिक गैस की अधिकतम आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। उर्जा के प्रमुख निर्यातक देश ईरान, सउदी अरब, ईराक, कुवैत और यूएई के लिए यह एक मात्र प्रमुख समुद्री व्यापारिक रास्ता है। यह रास्ता ओमान और ईरान के बीच स्थित फारस की खाड़ी में है। इस मार्ग का सबसे सकरा हिस्सा मात्र 21 मील चौड़ा है, जिससे यहां परिवहन कठिन होता है। यहां तेल टैंकरों पर सबसे ज्यादा हमले होते है। बावजूद वैश्विक उर्जा की सप्लाई की यह जीवन रेखा है।

जहाजों की सुरक्षा चुनौती केवल जीपीएस में गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। जहाजरानी कंपनियां रैंसवेयर सप्लाई चैन हमलों और जहाजों के इंजन प्रोपल्शन एवं नेविगेशन नियंत्रण प्रणालियों पर भी डिजिटल हमलों के खतरे बढ़ गए हैं। उपग्रह इंटरनेट और रिमोट निगरानी के उपयोग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इस कारण मार्गों पर साइबर हमलों की संख्या बढ़ गई है। इन इलेक्ट्रोनिक हमलों को प्रशिक्षित चालक दल इसलिए ठीक-ठीक नहीं समझ पाता है, क्योंकि उन्हें केवल ई-मेल फिशिंग और यूएसबी सुरक्षा का प्रशिक्षण देने तक सीमित रखा जाता है। जबकि वास्तविक समुद्री संकट तब पैदा होता है, जब नौका चालन प्रणाली को जैमिंग और स्पूफिंग तकनीक के जरिए भटकाने के प्रयास कर दिए जाते है। ऐसे में चालक दल को यह समझना कठिन होता है कि यह तकनीकि खराबी है अथवा साइबर हमला। ऐसी स्थिति इसलिए पैदा हो जाती है, क्योंकि सबकुछ डिजिटल कर दिया गया है। जबकि पारंपरिक नौवहन कौषल से जुड़ी षिक्षा लगातार कम हो रही है। इस कारण अनेक व्यापारिक जहाजों पर अब मानचित्र और कागजी संकेत रहते ही नहीं हैं। खगोलीय-

नौवहन का अभ्यास भी बहुत कम रह गया है। ऐसे में यदि इलेक्ट्रोनिक प्रणालियां बाहरी प्रभाव से गड़बड़ा दी जाती हैं तो चालक दल के पास वास्तविक स्थिति को जानने का कोई आधार नहीं रह जाता है।

भारत ने समुद्री मार्ग को पहचानने के लिए अपने उपग्रहों की संख्या विकसित कर ली है। इस श्रृंखला में उपग्रह IRNSS-1-ए, IRNSS 1-बी, IRNSS 1-सी, 1-डी, एवं 1-ई, जनवरी 2016 में और छठा आईआरएनएसएस 1-एफ मार्च 2016 में अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिए गए हैं। हालांकि नौवहन सेवाएं चार उपग्रहों से भी संचालित की जा सकती रही हैं, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निगरानी प्रणाली को दोषमुक्त व सटीक बनाए रखने के लिए पूरे जीपीएस को 09 उपग्रहों से जोड़ दिया है। इन उपग्रहों में परस्पर अंतर्संबंधों के चलते नाविक नामक यह प्रणाली भूमि आकाश व समुद्री सतहों पर दिशा व दूरी की सूचनाएं जहाजों के चालक दल को देती है। यह प्रणाली चालक दलों को दिशाओं का ज्ञान कराएगी,वहीं वाहनों के भीतर के दृष्य व श्रृव्य, चित्र व संकेत भी उपलब्ध कराती है। भटके हुए समुद्री जहाजों को इस कारण दिशा-निर्देशित करना आसान होता है।

केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की घटती साख !

रघु ठाकुर

27 फरवरी 26 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि को ईडी के द्वारा दायर प्रकरण पर चार्ज लगाने के पूर्व ही मुक्त कर दिया। अदालत ने अपने लंबे आदेश में ईडी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की खामियों पर चर्चा की तथा उसने कहा कि ईडी के पास न तो प्रमाण हैं और न ही वह प्रमाणिक ढंग से आरोप सिद्ध कर सकी है। इस घटना ने फिर एक बार ईडी को कठघरे में खड़ा किया है। वैसे भी पिछले दिनों जो प्रकरण ईडी ने दायर किये और राजनैतिक नेताओं व लोगों को लंबे समय तक जेल में रखा, वे अधिकांश सिद्ध नहीं पाये गये। हालात इतने बदतर हैं कि ईडी के द्वारा बनाये गये प्रकरणों में मुश्किल से 3 प्रतिशत प्रकरणों में ही आरोपियों को दंडित किया जा सका है। वह भी छोटे-मोटे अधिकारी, कर्मचारियों को। राजनेताओं में तो शायद ही कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली रहा हो जिसे ईडी, सीबीआई की विशेष अदालत ने दंडित किया हो, कम से कम मेरी जानकारी में तो नही है। इसके पूर्व भी हेमंत सोरेने मुख्यमंत्री झारखंड, ए. राजा (डीएमके) और ऐसे ही अनेक नाम लिये जा सकते हैं जिनमें कई-कई माह तक राजनेताओं को जेल में डाला गया, कई के राजनैतिक कैरियर नष्ट हो गये और उन्हें अनावश्यक सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में अपमानित व लज्जित होना पड़ा और अंत में ईडी, सीबीआई के मुकदमे खारिज हो गये। हालांकि यह भी आश्चर्यजनक है कि इसी सीबीआई के जज जितेन्द्र सिंह सिंह जिन्होंने अब यह फैसला दिया है, हालाँकि वे ही लगातार इन

आरोपियों के जमानत आवेदनों को निरस्त भी करते रहे और ईडी को रिमांड देते रहे, जिससे अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसौदिया या इसके पहले संजय सिंह को इसी प्रकार लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। होना तो यह चाहिए कि ऐसे गंभीर मामलों में यह कानून बने कि ईडी को या सीबीआई को व्यक्तिगिरफ्तार करते ही और कोर्ट में पेश करते ही चार्ज शीट पेश करने की अनिवार्यता हो। ताकि न्यायालय चार्ज लगाते समय प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रमाणिक निर्णय कर सके और इन ईडी या सीबीआई जैसे संस्थानों को रिमांड मांगने की जरूरत ही न पड़े। कोई भी व्यक्ति जो बाद में निरपराध सिद्ध हो, उसे अनावश्यक जेल में न रहना पड़े। हालांकि ऐसे राजनैतिक आरोपों का चलन पहले भी रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा नियंत्रित ईडी की कार्यवाही जो सिद्ध नहीं हुई जिसके कारण दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ा और इस्तीफा भी देना पड़ा था। बाद में चुनाव में उनकी सरकार भी चली गई। पूर्व में केजरीवाल की संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से स्व. मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2जी स्पेक्ट्रम के घोटाले की बात कही गई थी उसमें 2 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में कई आईएएस अफ्सरों, मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता स्व. करूणानिधि की बेटी सांसद कनीमोझी को जेल में रहना पड़ा था और बाद में दोष भी सिद्ध नहीं हुआ। परंतु केन्द्र से मनमोहन की सरकार व दिल्ली से शीला दीक्षित की सरकार चली गई और अरविन्द केजरीवाल उससे लाभ उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तथा भाजपा ने उसका प्रचार कर बाद में दिल्ली में सरकार बनाई और नरेन्द्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने। अगर उसके और पुराने इतिहास में जाएं तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, बी.पी. सिंह ने बोफोर्स घोटाले को उठाया व मुद्दा बनाया। बाद में राजीव गांधी की सरकार चली गई। बी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने परंतु कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ और सभी आरोपी बरी हो गये। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में जब कारगिल में घुसपैठ हुई और इन घुसपैठियों को निकालने के लिये भारतीय सेना भेजी गई तो वही बोफोर्स तोपें कारगर साबित हुईं, और इनकी प्रशंसा हुई। इन घटनाओं से दो निष्कर्ष निकलते हैं, एक-आजकल राजनेता और कारपोरेट मिलकर अपने प्रतिद्वंद्वी को बदनाम करने, गिराने और राजनैतिक लाभ के लिये झूठे प्रकरण उठाते हैं। इसमें दुनिया की बड़ी-बड़ी कारपोरेट कंपनियों का अंतर युद्ध प्रमुख भूमिका अदा करता है। जिस कंपनी को ठेका नहीं मिल पाता वह कंपनी 500-1000 करोड़ रूपया ऐसे झूठे अभियानों पर खर्च करती और सुनियोजित मुहिम चलाती है, सरकार को गिराती व बनाती है और फिर सरकार बदलने के बाद, अपनी लागत की वसूली करती है

व मुनाफा कमाती है। देश की जनता मीडिया के प्रचार में वह जाती है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि राजनीति व राजनैतिक व्यक्तियों की साख आम जनता में इतनी गिर चुकी है कि उनके विरूद्ध लगाये गये प्रत्येक आरोप को देश सही मान लेता है। यह तो केवल गांधी ही है जिनके विरु द्ध लगभग 80 साल से देश की कुछ संस्थायें और पिछले 11-12 वर्षों से सरकार के संरक्षण में कानाफूसी, सोशल मीडिया, अखबारी बयान और हर प्रकार से

झूठ व निंदा का अभियान चलाया जा रहा है, परंतु गांधी का सम्मान और सत्य शास्वत है। भारतीय राजनीति व नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी साख इतनी गिरी हुई और कमजोर क्यों है? अब यह सिद्ध हो चुका है और जनमानस में स्वीकार तथ्य हो चुका है कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थायें जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने तोता कहा था वस्तुतः तोता ही है। वह तत्कालीन सरकार के अपने मालिकों की भाषा बोलते हैं। कटु सत्य तो यह है कि ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता आम जनमानस में समाप्त हो चुकी है। वह जिनके विरूद्ध कार्यवाही करते हैं उस पर सामान्य प्रतिक्रिया होती है तथा आम जनमानस में यह धारणा बनती है कि फंसाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की साख व प्रमाणिकता इतनी गिर चुकी है कि अब उनके किसी भी कार्यवाही को आमजन सत्ता के द्वारा की गई कार्यवाही ही मानता है। यहाँ तक कि अगर वह कोई सच कार्यवाही भी करेंगे तो भी वह आम जनमानस में झूठी मानी जायेगी। न्यायपालिका में अपने अभियोजन को सिद्ध करने की उनकी दर भी लगभग नगण्य है, याने मात्र 3 प्रतिशत। यहां तक की पुलिस जो बदनाम संस्था है, उसके अभियोजन की सफलता दर ईडी, सीबीआई से कई गुना अधिक है। अब यह भावना देश में बन रही है कि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की उपयोगिता शून्य हो चुकी है और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न आम जनमानस में है कि जब न्यायपालिका ईडी, सीबीआई पुलिस की कार्यवाही को न केवल गलत ठहराती है बल्कि उनकी विवेचना और अभियोजन में गंभीर त्रुटियां इंगित करती है जिससे आरोपित अपराधी निर्दोष बरी होते हैं, तो न्यायपालिका इन जिम्मेवार अधिकारियों के विरूद्ध झूठे अभियोजन और पीड़ित पक्षकारों को क्षतिपूर्ति के लिये आदेश क्यों नहीं करती? ऐसे गैर जिम्मेवार और सत्ता निष्ठा वाले अधिकारियों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए जिन्होंने न केवल झूठे प्रकरण बनाये या किसी को बचाने के लिये दबाने का अपराध किया है। 1990 में हवाला कांड हुआ था जिसमें दानदाताओं ने एक साथ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, जेकेएलएफ के मुखिया अमानउल्ला खान और अन्य अनेक सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को पैसे दिए थे और उन सभी पर आरोप लगे थे। यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा के बड़े-बड़े बयान अखबारों व पत्रिकाओं में उन दिनों छपते थे जिनमें कहा जाता था कि मैं स्वतः इसका निरीक्षण करूंगा, उनकी निगरानी में जांच व कार्यवाही होगी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि इस कांड के आरोपों से मुझे रात में नींद नहीं आती और अनेक लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए। यह प्रकरण जिस डायरी की सूची के आधार पर दर्ज हुए थे हमारे देश की महान जांच एजेंसी सीबीआई उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई और जिस प्रकरण की जांच की निगरानी भारत के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे उस प्रकरण को एक जिला स्तर के जज ने यह लिखकर समाप्त कर दिया कि अकेले डायरी कोई साक्ष्य नहीं होती जब तक कि कोई अन्य उसकी पुष्टि न करे। याने भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च अदालत को इस नजीर का पता नहीं था कि अकेले डायरी प्रमाण नहीं मानी जाती। कुल मिलाकर देश की सरकारें, जांच एजेंसियां और कुछ हद तक न्यायपालिका भी आम जनमानस में विश्वसनीयता खो चुकी है, यह गंभीर चिंता

ट्रंप ने विश्व में मचाई तबाही

ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में मची उथल-पुथल

विजया पाठक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक साल में पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। जब से वह राष्ट्रपति बने हैं तबसे पूरे विश्व में उथल-पुथल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरूआत के साथ ही अमेरिका फर्स्ट नीति ने वैश्विक व्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी है। हाल ही में ईरान पर हुए हमले ने तो ट्रंप की दादागिरी उजागर हो गई है। ट्रंप अपनी दादागिरी पूरे विश्व में थोपना चाहते हैं। खासकर छोटे देशों पर तो अनुचित कार्यवाही से नहीं चूक रहे हैं।

ईरान के खिलाफ चल रहा मौजूदा अभियान ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे आक्रामक और जोखिम भरी कार्रवाई मानी जा रही है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इसका खुला उद्देश्य ईरान की सरकार को गिराना है।

अपने हितों को साधने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। ईरान के खिलाफ चल रहा मौजूदा अभियान ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे आक्रामक और जोखिम भरी कार्रवाई मानी जा रही है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इसका खुला उद्देश्य ईरान की सरकार को गिराना है। यह फैसला उन्होंने बिना कांग्रेस की मंजूरी और बिना लंबी सार्वजनिक बहस के लिया। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के बाद पहली

बार मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा हुआ। 9/11 के बाद जार्ज डब्ल्यू बुश ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। बाद में बराक ओबामा ने ड्रोन हमले किए। लेकिन ये अभियान पहले से मंजूर या चल रहे युद्ध क्षेत्रों तक सीमित थे। इसके उलट ट्रंप ने नए मोर्चे खोले। उन्होंने क्रिसमस के दिन नाइजीरिया में हमला कराया, कैरिबियाई इलाके में ड्रग तस्करी करने वाली नावों को डुबोया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कराकस से पकड़ लिया। ट्रंप की रणनीति साफ है। जमीनी सैनिक नहीं भेजना, लंबे समय तक किसी देश में फंसे नहीं रहना, और बहुत कम समय में भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना। इसे वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए जरूरी बताते हैं। सनकी ट्रंप ने सभी के लिए हालात बेकाबू कर दिये हैं। अपनी रणनीतियों को थोपकर वह जताना चाहता है कि अमेरिका ही सबसे ताकतवर है।

ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाने की इच्छा व्यक्तकी थी। अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, पनामा नहर और गाजा पट्टी को भी अपने देश में मिलाने या उन पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया है।

ट्रंप की रणनीति साफ है। जमीनी सैनिक नहीं भेजना, लंबे समय तक किसी देश में फंसे नहीं रहना, और बहुत कम समय में भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना। इसे वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए जरूरी बताते हैं। सनकी ट्रंप ने सभी के लिए हालात बेकाबू कर दिये हैं।

12 महीने में 7 देशों पर किया हमला, अब 8वीं की तैयारी : डोनाल्ड ट्रंप ने एक साल में सात देशों पर सैन्य कार्रवाई कर रिकार्ड बनाया, 2025 में एयर स्ट्राइक के

मामले में वे बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल से भी आगे रहे। खुद को युद्ध विरोधी बताने वाले ट्रंप ने ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरूकिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साल में सात देशों पर सैन्य कार्रवाई कर रिकार्ड बनाया, 2025 में एयर स्ट्राइक के मामले में वे बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल से भी आगे रहे। आधुनिक अमेरिकी इतिहास में शायद ही किसी राष्ट्रपति ने उतने देशों पर सैन्य हमले कराए हों, जितने डोनाल्ड ट्रंप ने किए। उन्होंने सात अलग-अलग देशों पर कार्रवाई की। इनमें से तीन देश ईरान, नाइजीरिया और वेनेजुएला ऐसे थे, जहां इससे पहले अमेरिका ने कभी सैन्य हमला नहीं किया था. साल 2025 में ट्रंप ने जितने हवाई हमलों को मंजूरी दी, उतने चार साल में राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नहीं दिए थे। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू की, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह ऐसे परमाणु हथियार बना रहा है जो

अमेरिकी सहयोगियों के लिए ख़तरा हैं और जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं।

यह मामला इसलिए खास है क्योंकि ट्रंप ने खुद को चुनाव के दौरान युद्ध विरोधी नेता के तौर पर पेश किया था। उनका कहना था कि वे अमेरिका को नए युद्धों में नहीं उलझाएंगे। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद हैं। ईरान पर हमले को गलत और घिनौना बताया है। दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 2023 में एक आर्टिकल में कहा था कि ट्रंप की सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धि यह थी कि उन्होंने कोई नया युद्ध शुरूनहीं किया। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि बातचीत की कोशिशें असफल रहीं, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू किया गया यह

युद्ध अमेरिकी जानों की कीमत के लायक है। यह बहस ट्रंप के पूरे कार्यकाल में जारी रहने की संभावना है।

आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पूरे विश्व में व्यापारिक, आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। जो देश युद्ध भी नहीं लड़ रहे वह भी इसकी चपेट में आ गये हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यह भी है कि किसी को पता नहीं है कि यह युद्ध और कब तक चलेगा।

आर्थिक और व्यापार युद्धः ट्रंप के प्रशासन ने सहयोगियों और विरोधियों दोनों पर सीमा शुल्क लगा दिया है, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने नाटो और अन्य सुरक्षा गठबंधनों के प्रति प्रतिबद्धता को कम किया है, जिससे यूरोप की सुरक्षा संरचना कमजोर हो रही है।

युद्ध का भारत पर प्रभाव

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध भारत के लिए मुसीबत लेकर आया है। यही कारण है कि आज तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बयान नहीं आया है। संबंधों की बात करें तो इजराइल और ईरान से भारत के संबंध बेहतर हैं। अमेरिका से भले ही कुछ तनातनी चल रही है। लेकिन यहां एक बात जरूर गौर करने वाली है कि ईरान हमेशा से भारत का अच्छा मित्र रहा है। हर मुसीबत में ईरान ने साथ दिया है। आज जब ईरान मुसीबत में है तो भारत न्यूट्रल की स्थिति में है। वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की हत्या कर दी गई है। ईरान युद्ध में जल रहा है। भारत कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहां विपक्ष इस मामले पर मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जहां तक व्यापारिक हितों की बात करें तो अभी भले ही असर नहीं हो रहा है लेकिन युद्ध और आगे चलने से भारत की मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि मोदी अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गये हैं। भारत के लिए यह एक जटिल स्थिति है जहाँ एक ओर रक्षा और तकनीक में बेहतर रिश्तों की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर व्यापार समझौते में चुनौतियाँ और अमेरिकी दबाव का जोखिम बना हुआ है। ट्रंप के आने से पारंपरिक वैश्विक व्यवस्था चरमरा रही है। यह दौर अपेक्षा से कहीं अधिक उथल-पुथल का है, जहाँ पुरानी सुरक्षा गारंटी कमजोर हो रही है और देशों को अपने बलबूते पर नई रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं। आज भारत ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है कि वह न तो युद्ध के पक्ष में दिखाई दे रहा है और न ही विरोध में।

मोदी की चुप्पी के क्या मायने?: राहुल गांधी पहले भी विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस कमजोर हो रही है। कांग्रेस ने भी इस पर सपोर्ट किया और कहा कि सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए।

पारंपरिक मेलों पर संकटः सुरक्षा और आजीविका के बीच संतुलन की तलाश

जगराम गुर्जर

भारत के पारंपरिक मेले केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, वे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का जीवंत हिस्सा हैं। गांव-गांव, शहर-शहर लगने वाले ये मेले सदियों से लोगों के मेल-मिलाप, लोक संस्कृति और आजीविका का आधार रहे हैं। यहां झूले लगाने वाले, खिलौने बेचने वाले, बर्तन, चूड़ी, हस्तशिल्प बेचने वाले दुकानदार, बुनकर, लोक कलाकार और छोटे कुटीर उद्योगों से जुड़े हजारों परिवार अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं लेकिन आज यह पारंपरिक कारोबार गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। विशेष रूप से गुजरात में तो स्थिति ऐसी बन गई है कि मेले लगभग समाप्ति की ओर हैं। अन्य राज्यों में भी कड़े नियमों की आशंका से मेला आयोजकों और झूला संचालकों के बीच असुरक्षा का माहौल है। राजकोट में एक गेमिंग जोन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस हादसे के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त नियम लागू किए। जन सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन नियम बनाते समय इस बात पर शायद ध्यान ही नहीं दिया गया कि राजकोट की घटना एक बंद, पक्के और अवैध गेमिंग जोन में हुई थी जबकि पारंपरिक मेले और झूले खुले वातावरण में अस्थायी ढांचे में लगाए जाते हैं। खुले मेलों के झूले न तो पक्के भवनों में होते हैं, न ही उनमें जटिल बिजली व्यवस्था या आग पकड़ने वाली बनावट होती हैं। इसके बावजूद नए नियमों का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं छोटे मेला आयोजकों और झूला संचालकों पर पड़ा है। नए प्रावधानों के तहत महंगे इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, भारी बीमा कवर, जटिल लाइसेंस प्रक्रिया और बार-बार निरीक्षण जैसी शर्तें लागू कर दी गई हैं। छोटे स्तर पर काम करने वाले ये लोग पहले ही भारी कर्ज लेकर अपने झूले खरीदते हैं। उनके लिए महंगे प्रमाण पत्र और बीमा प्रीमियम जुटाना लगभग असंभव है। परिणामस्वरूप, गुजरात में मेले लगने बंद हो गए हैं, झूले खुले मैदानों में जंग खा रहे हैं और हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी

का संकट खड़ा हो गया है। मेले और झूले वालों में से अधिकांश के पास इस पारंपरिक काम के अलावा कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है। पीढ़ियों से यही इनका पेशा रहा है। यह केवल व्यवसाय नहीं, इनकी पहचान भी है। यदि यह बंद होता है तो केवल रोजगार ही नहीं, एक जीवंत लोक परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। गौर करने वाली बात है कि कोई भी मेला आयोजक या झूला संचालक सुरक्षा नियमों को हटाने की मांग नहीं कर रहा। बंद गेमिंग जोनों के लिए कठोर नियम आवश्यक हैं और उनका पालन होना चाहिए लेकिन खुले मेलों के पारंपरिक झूलों के लिए अलग, सरल और व्यवहारिक नियम बनाए जाने चाहिए।

सरकार यदि श्रेणीकरण (कैटेगराइजेशन) की व्यवस्था करे तो भी झूले वालों को राहत मिल सकती है। जैसे बड़े यांत्रिक राइड्स और छोटे पारंपरिक झूलों के लिए अलग-अलग मानक बनाए जाएं तो इससे संतुलन बन सकता है। इसके साथ ही समूह बीमा योजना, कम लागत निरीक्षण प्रणाली और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम उठाए जाएं तो मेला व्यवसायी सुरक्षा मानकों का पालन भी कर सकेंगे और अपनी आजीविका भी बचा पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए नियमों को लागू करते समय ग्रेस पीरियड दिया जाए। यदि दो से तीन वर्षों का समय दिया जाए तो छोटे संचालक धीरे-धीरे आवश्यक प्रावधानों को पूरा कर सकते हैं। अचानक लागू की गई कठोर शर्तों ने पूरे तंत्र को ठप कर दिया है। हाल में सूरजकुंड में झूला टूटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी सामने आई। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से चिंताजनक हैं लेकिन हर हादसे का पूरा दोष झूला संचालक पर डाल देना न्यायसंगत नहीं है। यह भी जांच का विषय है कि कहीं झूलों के निर्माण में तकनीकी खामी या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं था। आज देश में अनेक झूला निर्माता कार्यरत हैं। क्या उनके निर्माण मानकों की नियमित जांच होती है? क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर झूला तकनीकी कसौटियों पर खरा उतरता है? यदि निर्माण स्तर पर ही त्रुटि रह जाए तो उसका खामियाजा अंतिम संचालक और आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए समस्या का समाधान केवल संचालन स्तर पर कठोरता बढ़ाने में नहीं है बल्कि निर्माण से लेकर संचालन तक एक संतुलित और व्यवहारिक निगरानी व्यवस्था बनाने में है।

पारंपरिक मेलों को समाप्त होने देना केवल आर्थिक क्षति नहीं होगी बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी आघात होगा। आज जब बड़े मॉल और डिजिटल मनोरंजन के साधन तेजी से बढ़ रहे हैं, तब भी मेले लोगों को खुला, सामुदायिक और पारिवारिक मनोरंजन प्रदान करते हैं। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को संबल देने में इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आवश्यक है कि सरकार, प्रशासन और मेला आयोजकों के प्रतिनिधि मिलकर एक व्यवहारिक नीति तैयार करें। एक ऐसी नीति जो भले ही सुरक्षा से समझौता न करे लेकिन छोटे व्यवसायियों को काम करने से भी नहीं रोके। यदि समय रहते संतुलित निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाली पीढ़िया शायद केवल किताबों में पढ़ेंगी कि कभी हमारे गांव-शहरों में रंग-बिरंगे मेले लगते थे जिनमें बच्चों की हंसी और लोकगीतों की गूंज होती थी। सुरक्षा और आजीविका के बीच संतुलन ही इस संकट का वास्तविक समाधान है। यही समय की मांग है।

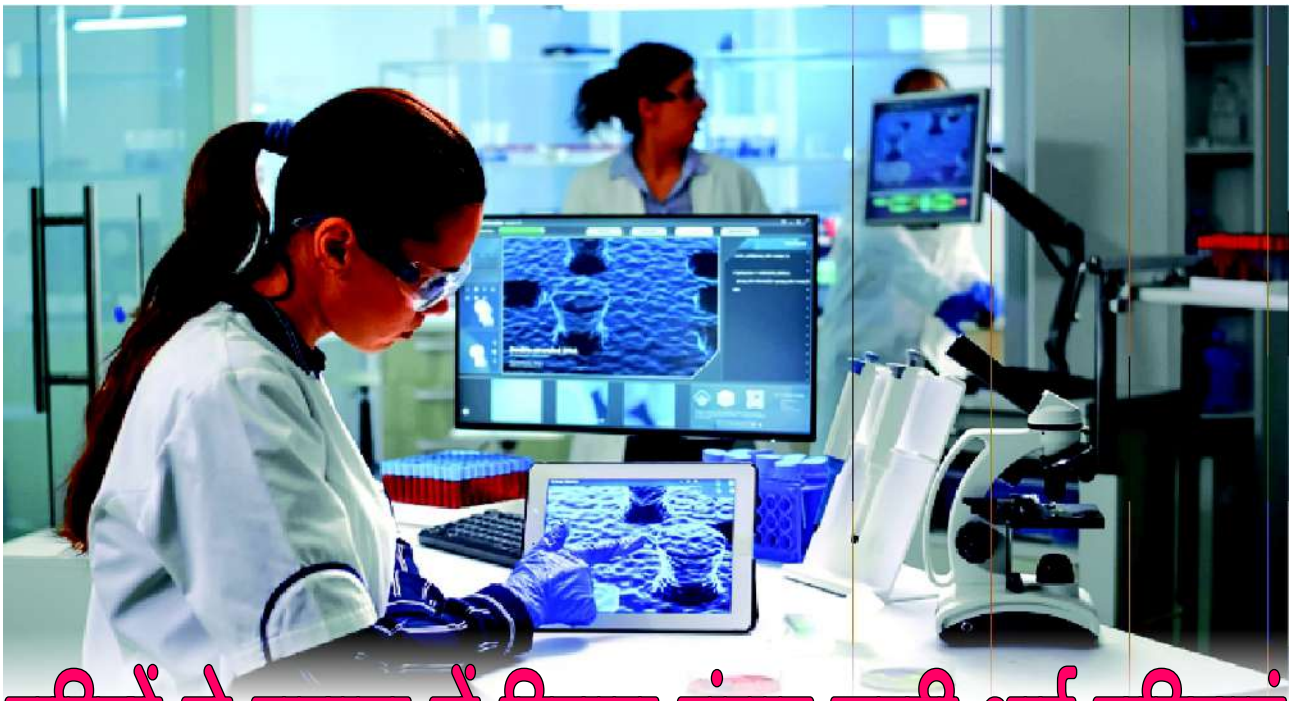

सदियों से समाज में विज्ञान संचार करती आई महिलाएं

डॉ. विजय गर्ग

विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, यह समाज की सोच, जीवनशैली और प्रगति से जुड़ा हुआ है। विज्ञान के विकास में जहाँ पुरूष वैज्ञानिकों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, वहीं सदियों से अनेक महिलाओं ने न केवल वैज्ञानिक खोजों में योगदान दिया, बल्कि विज्ञान को समाज तक पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी किया। विज्ञान संचार के इस ऐतिहासिक सफर में महिलाओं की भूमिका प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी रही है। प्राचीन काल में भी महिलाओं ने ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में गार्गी वाचक्नवी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने दार्शनिक और वैज्ञानिक चिंतन को समाज में चर्चा का विषय बनाया। उनके प्रश्न और तर्क उस समय के ज्ञान-विज्ञान की गहराई को जनमानस तक ले गए। यह विज्ञान संचार का ही एक रूप था, जहाँ जिज्ञासा और संवाद के माध्यम से ज्ञान का विस्तार हुआ। आधुनिक युग में विज्ञान संचार को नई दिशा देने वाली महिलाओं में मैरी क्यूरी का नाम अग्रणी है। उन्होंने रेडियम की खोज के माध्यम से विज्ञान को आम लोगों के जीवन से जोड़ा। वहीं जेन गुडॉल ने अपने शोध और पुस्तकों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण का संदेश विश्वभर में फैलाया। उनकी सरल भाषा और संवेदनशील प्रस्तुति ने विज्ञान को मानवीय दृष्टिकोण से जोड़ दिया।

भारत में भी विज्ञान संचार के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति युवाओं में उत्साह जगाया। उनकी जीवन यात्रा ने यह संदेश दिया कि विज्ञान किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार टेस्सी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने न केवल रक्षा विज्ञान में योगदान दिया बल्कि अपने व्याख्यानों और संवादों के माध्यम से विज्ञान को समाज के निकट लाने का कार्य किया। डिजिटल युग में विज्ञान संचार के नए मंच उभरे हैं। सोशल मीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे माध्यमों पर अनेक महिला वैज्ञानिक और शिक्षिकाएँ जटिल वैज्ञानिक विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर रही हैं। इससे विज्ञान केवल किताबों तक सीमित न रहकर आम जन-जीवन का हिस्सा बन रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान महिला डाक्टरों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सही जानकारी पहुँचाकर समाज में वैज्ञानिक सोच को मजबूत किया।

महिलाओं द्वारा विज्ञान संचार का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर बच्चों और युवतियों, के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। जब कोई लड़की किसी महिला वैज्ञानिक को मंच पर देखती है, तो उसके भीतर भी विज्ञान के प्रति आत्मविश्वास जागृत होता है। इस प्रकार विज्ञान संचार केवल जानकारी देना नहीं,

बल्कि सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया भी है। आज आवश्यकता है कि विज्ञान संचार में महिलाओं की भूमिका को अधिक मान्यता और समर्थन मिले। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और मीडिया संस्थानों को ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। विज्ञान तब ही सशक्तबनता है जब वह समाज के हर वर्ग तक पहुँचें और इस सेतु का निर्माण सदियों से महिलाएँ करती आई हैं।

प्राचीन कालः लोक ज्ञान की संरक्षिकाएँ

इतिहास के शुरु आती दौर में विज्ञान आज की तरह प्रयोगशालाओं में बंद नहीं था। वह जीवन जीने की कला थी।

घरेलू उपचार और वनस्पति विज्ञानः प्राचीन समाजों में महिलाएं ही प्राथमिक चिकित्सक थीं। उन्हें जड़ी-बूटियों के रासायनिक गुणों और उनके प्रभाव का गहरा ज्ञान था, जिसे वे गीतों और कहानियों के जरिए समाज में प्रसारित करती थीं।

कृषि विज्ञानः बीजों का चयन, मिट्टी की उर्वरता और मौसम चक्र की समझ महिलाओं ने ही विकसित की और इसे एक सामूहिक ज्ञान बनाया।

मध्यकालः चुनौतियों के बीच संचार

मध्यकाल में जब शिक्षा पर पुरूषों का एकाधिकार बढ़ने लगा, तब भी महिलाओं ने हार नहीं मानी।

पांडुलिपियाँ और अनुवादः कई विदुषी महिलाओं ने वैज्ञानिक ग्रंथों का अनुवाद किया ताकि वे आम लोगों की समझ में आ सकें।

रसोई एक प्रयोगशालाः खाद्य संरक्षण और किण्वन जैसी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को महिलाओं ने 'पारंपरिक व्यंजनों' के रू प में समाज में स्थापित किया।

आधुनिक युग और वैज्ञानिक चेतना

19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने औपचारिक रूप से विज्ञान संचारक की भूमिका निभाई,

मैरी क्यूरी और इरेन्ज जूलियट-क्यूरीः इन्होंने न केवल शोध किया, बल्कि आम जनता और सैनिकों के बीच रेडियोलॉजी के महत्व को पहुँचाया।

राचेल कार्सनः उनकी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने पर्यावरण विज्ञान को हर घर की चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को इतनी सरलता से समझाया कि पूरी दुनिया में पर्यावरण आंदोलन शुरूहो गया।

भारतीय परिप्रेक्ष्यः एक अनूठी विरासत

भारत में विज्ञान संचार की जड़ें बहुत गहरी हैं:

लोक परंपराएंः दादी-नानी के बटुए से लेकर लोक कथाओं तक, विज्ञान हमेशा मौजूद रहा।

आधुनिक संचारकः आज भारत में ईरावती कर्वे जैसी नृवंशविज्ञानी और गगनदीप कांग जैसी वैज्ञानिक जटिल चिकित्सा विज्ञान को सरल भाषा में जनता तक पहुँचा रही हैं।

आज की डिजिटल क्रांति

आज के युग में सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और ब्लाग्स के माध्यम से महिलाएं विज्ञान को लोकतांत्रिक बना रही हैं। वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों को साझा कर रही हैं, बल्कि समाज में व्याप्त अधविश्वास को वैज्ञानिक तर्क से चुनौती भी दे रही हैं।

महिलाओं ने विज्ञान को केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसे जीया और बाँटा है। उनका योगदान केवल प्रयोगशाला की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने विज्ञान को समाज की भाषा दी है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विज्ञान की ज्योति को जन-जन तक पहुँचाने में महिलाओं का योगदान अमूल्य रहा है। उन्होंने संवाद, लेखन, शिक्षण और शोध के माध्यम से विज्ञान को केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अंग बनाया है।

इन्दौर में 1857 की क्रांति के नायक भगीरथ सिलावट और सआदत खा

इंदौर में 1857 की क्रांति में सैनिक अधिकारी भगरीथ सिलावट और सआदत खाँ प्रमुख भूमिका में थे। उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका और लम्बा संघर्ष किया। अंग्रेजों ने दमनचक्र चलाया और मृत्युदण्ड दिया। योजना के अनुसार रेसीडेन्सी पर 1 जुलाई 1857 को सुबह 8 बजकर 40 मिनिट पर आक्रमण किया गया। शुरुआत इन्दौर के सैनिकों ने की। रेसीडेन्सी और अंग्रेजों की रक्षा के लिये जो सैनिक इन्दौर भेजे गये थे उन्होंने रेसीडेन्सी पर ही गोली चलाना शुरू कर दिया।

इन्दौर में 1857 की क्रांति में सैन्य अधिकारी भगीरथ सिलावट ने अग्रणी की भूमिका निर्वाह की। क्रांति का बिगुल फूंकने वाले इन नायकों ने लम्बा संघर्ष किया। अंग्रेजों ने दमनकारी प्रयासों के अंतर्गत इन्हें मृत्युदण्ड दिया।

इन्दौर में 1857 क्रांति की तैयारी पहले से हो चुकी थी। 13 मई 1857 को इन्दौर रेसीडेन्सी में आगरा से तार आया कि मेरठ में क्रांति हो गयी है। यह सूचना जल्दी ही शहर में फैल गयी और इन्दौर का मनोबल बढ़ा। जून महीने में क्रांतिकारियों का सघन अभियान चला। 6 जून को नीमच छावनी में, 10 जून को महीदपुर छावनी में क्रांति आरम्भ हुई। महीदपुर में क्रांति की सफलता से इन्दौर के क्रांतिकारी उत्साहित हो गये।

जून के अन्त तक इन्दौर में तैयारियां पूरी हो गयी थीं। क्रांतिकारी सिर्फ उपयुक्त अवसर की तलाश में थे और यह अवसर जल्दी ही आ गया। क्रांति के महत्वपूर्ण नेताओं, सआदत खाँ, वंशगोपाल, अर्राराव सिंह, भगीरथ, नवाब वारिस मोहम्मद खाँ, मौलवी अब्दुल समद और अन्य लोगों ने

इन्दौर में क्रांति का दिन 1 जुलाई निश्चित किया।

योजना के अनुसार रेसीडेन्सी पर 1 जुलाई 1857 को सुबह 8 बजकर 40 मिनिट पर आक्रमण किया गया। शुरुआत इन्दौर के सैनिकों ने की। रेसीडेन्सी और अंग्रेजों की रक्षा के लिये जो सैनिक इन्दौर भेजे गये थे उन्होंने रेसीडेन्सी पर ही गोली चलाना शुरू कर दिया। कर्नल ट्रेवर्स ने भोपाल की घुड़सवार सेना के 75 घुड़सवारों को क्रांतिकारियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया लेकिन सिर्फ 6 घुड़सवारों ने उसकी आज्ञा का पालन किया।

रेसीडेन्सी पर 1 जुलाई 1857 को सुबह 8 बजकर 40 मिनिट पर आक्रमण किया गया। शुरुआत इन्दौर के सैनिकों ने की। रेसीडेन्सी और अंग्रेजों की रक्षा के लिये जो सैनिक इन्दौर भेजे गये थे उन्होंने रेसीडेन्सी पर ही गोली चलाना शुरू कर दिया। कर्नल ट्रेवर्स ने भोपाल की घुड़सवार सेना के 75 घुड़सवारों को क्रांतिकारियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया लेकिन सिर्फ ६ घुड़सवारों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। होल्कर की तोपें रेसीडेन्सी की सुरक्षा के लिये तैनात थीं। इन तोपों ने रेसीडेन्सी भवन पर गोले बरसाना शुरू कर दिया क्रांतिकारी बाजार से होते हुए यूरोपियनों के आवास पर गये। उन्होंने इन आवासों में आग लगा दी तथा उनके निवासियों को मौत के घाट उतार दिया। रेसीडेन्सी से क्रांतिकारियों ने नौ लाख रुपये बरामद किये इसके अलावा वे होल्कर की कुछ तोपों को अपने साथ ले गये। क्रांतिकारियों के इस दल का नेतृत्व किया सआदत खां ने।

होल्कर की तोपें रेसीडेन्सी की सुरक्षा के लिये तैनात थीं। इन तोपों ने रेसीडेन्सी भवन पर गोले बरसाना शुरू कर दिया क्रांतिकारी बाजार से होते हुए यूरोपियनों के आवास पर गये। उन्होंने इन आवासों में आग लगा दी तथा उनके निवासियों को मौत के घाट उतार दिया। रेसीडेन्सी से क्रांतिकारियों ने नौ लाख रुपये बरामद किये इसके अलावा वे होल्कर की कुछ तोपों को अपने साथ ले गये। क्रांतिकारियों के इस दल का नेतृत्व किया सआदत खां ने। इनके अन्य प्रमुख साथी थे भगीरथ सिलावट (सैनिक अधिकारी), नवाब वारिस मोहम्मद खां (भोपाल रियासत), वंश गोपाल कमान्डेन्ट, शेर खां जमादार, मौलवी अब्दुल समद (फारसी का अध्यापक), नन्हें खाँ, मोहम्मद अली तोपची, महीदपुर रिसाले का कमान्डर रहमतुल्ला खाँ और दुर्गा प्रसाद

सैन्याधिकारी।

यहाँ से 3000 क्रांतिकारियों ने आगरा-मुम्बई मार्ग से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 12 जुलाई की सुबह क्रांतिकारी ब्यावरा पहुंच गये। वहाँ से राघौगढ़ होते हुए शिवपुरी पहुंचे। इस क्रांति अभियान के दौरान अंग्रेजों ने फूट डालने की साजिश रची। किसी ने सआदत खाँ को बताया कि काली वर्दी वाले दस्ते महाराजा के द्वारा भेजे गये हैं और भगीरथ के साथ मिलाकर वे सआदत खाँ को बन्दी बनाना चाहते हैं। शंकित हो सआदत खाँ ने भगीरथ को शिवपुरी में बन्दी बना लिया। यहां मुरार और महू के क्रांतिकारियों ने सीख-समझाईश कर भगीरथ को मुक्त कराया। सआदत खाँ अपना यह विश्वसनीय साथी खो चुके थे। स्वाभिमानी भगीरथ वहाँ और नहीं रुके, दिल्ली की ओर बढ़ गये।

3 अगस्त को मुरार छावनी के क्रांतिकारी महाराजा सिंधिया से मिलना चाहते थे जिसकी उन्होंने अनुमति दे दी। मुरार में ही शाहजादा फीरोजशाह भी अपने साथियों के साथ इस दल में 28 अगस्त को आ मिले। क्रांतिकारियों ने सआदत खाँ की सहमति से फीरोजशाह को अपना प्रमुख सेनापति बनाया तथा सआदत खाँ को उसका उप-सेनापति। फीरोजशाह को इस अवसर पर 22 तोपों की सलामी दी गई। फिर क्रांतिकारी अपना आवश्यक प्रबंध करके दिल्ली की यात्रा पर रवाना हो गये। यह दल 6 सितम्बर की रात को चम्बल घाट पर पहुंचा। घोर वर्षा के कारण क्रांतिकारियों को नदी तट पर रुकना पड़ा। 14 सितम्बर को बाढ़ कम होने पर ही सुरक्षा सैनिक सामान सहित पार जा सके।

धौलपुर पहुँचने पर, नवाब वारिस मोहम्मद खाँ ने धौलपुर के राणा को लिखा कि वह केम्प पर आकार शाहजादा फीरोजशाह का स्वागत करें, क्रांति यात्रा में साथ चले। राणा इस बात पर सहमत नहीं हुए। धौलपुर पड़ाव पर अब क्रांतिकारियों की संख्या दो हजार तक बढ़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया। शाहजादा फीरोजशाह को धौलपुर राज्य का शासक घोषित कर दिया। क्रांतिकारी 18 सितम्बर तक धौलपुर में ही रहे और फिर आगरा की ओर चल दिये। आगरा से करीब छः मील दूर मानोवट नामक स्थान पर 10 अक्टूबर को क्रांतिकारियों की ब्रिटिश फोर्स से मुठभेड़ हुई। युद्ध में डेढ़ हजार क्रांतिकारी मारे गये, उनका सभी

सामान तोपें आदि छीन लिये गये जिसका मूल्य दस लाख रुपया था। पराजित क्रांतिकारी यहाँ-वहाँ बिखर गये।

इन्दौर की क्रान्ति का अग्रणी क्रांतिकारी भगीरथ 14 अगस्त को मोरार में सआदत खाँ से मुक्त होने के बाद पचास सवारों सहित दिल्ली के लिये चल दिये। उनके प्रमुख साथी थे- अमीर खाँ, करीम खाँ, महादेव ब्राह्मण, दाजी मराठा, मुरारी सईस, रमजान खाँ सवार तथा कासल। मथुरा से चलकर कोसीगांव, बेदल, बलवल, बल्लमगढ़ होते हुए भगीरथ अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बादशाह के ज्येष्ठ पुत्र मिर्जा खुर्रेश के साथियों से मुलाकात की। भगीरथ ने बादशाह को बताया कि वे इन्दौर में क्रांति कर दिल्ली आये हैं। भगीरथ और उनके साथी दिल्ली में लगभग 16-17 दिन रुके।

दिल्ली से लौटते समय, भगीरथ को बादशाह तथा शाहजादा ने अपने-अपने पत्र सीलबंद लिफाफे में, होल्कर महाराजा के लिये दिये। दिल्ली से इन्दौर लौटते समय देपालपुर के मामलतदार ने अपने पचास सैनिकों के साथ भगीरथ के दल को घेर लिया। साथियों सहित भगीरथ पकड़े गए और उन्हें इन्दौर लाया गया। भागीरथ के पैरों में बेड़ियां डाल दी गयीं। उन पर इन्दौर में मुकदमा न चलाकर उन्हें देपालपुर ले जाना तय हुआ। देपालपुर के पास मोरवर्दी नामक पहाड़ी पर इस रणबांकुर को फांसी दे दी गई।

उधर आगरा की मुठभेड़ व बिखराव के बाद सआदत खाँ अलवर आये और वहां सपरिवार एक वर्ष तक रहे। अलवर के बाद वे उज्जैन आये जहां अकबर खाँ के रूप में सेठ गंगाधर के यहाँ दो वर्ष तक नौकरी करते रहे। फिर सलुम्बर, गुड़ी और बांसावाड़ा में नाम बदलकर तेरह वर्ष बिताये और फिर उज्जैन आये। उस समय सआदत खाँ का पुत्र अहमद खाँ उनके साथ था। दुर्भाग्य से 1874 के जनवरी मास में बांसवाड़ा के जंगल में गुप्तचरों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके गाल पर तलवार की धार का निशान पहचान बना उसी से उनकी शिनाख्त हो सकी।

सआदत खाँ को दोषी करार देते हुए 7 सितम्बर 1874 को मृत्युदण्ड घोषित किया। 1 अक्टूबर 1874 को इन्दौर में इस देशभक्त को फांसी दे दी गयी। इन्दौर रेसीडेन्सी से उठी क्रांति की इस गूंज को उसी परिसर में दफन कर दिया गया।

Jharkhand child marriage crisis: Challenges and a glimmer of hope

Md Tabrez Alam

In Jharkhand, entrenched poverty, patriarchal social norms, and systemic gaps in child protection continue to push thousands of girls into early and forced marriages each year. Despite a measurable decline from 37.9 per cent* (NFHS-4, 2015-16) to 32.2 per cent (NFHS-5, 2019-21), prevalence of child marriage in Jharkhand remains substantially higher than the national average of 23.3 per cent (DHS Program; The Hindu Centre, 2022). This persistence reflects a crisis that undermines girls' fundamental rights to education, health, bodily autonomy and dignity.

The NFHS-5 data confirms the seriousness of the problem. More than one in three women aged 2024 years in Jharkhand were married before the legal age of 18, with rural girls (36.1 per cent) almost twice more affected than their urban counterparts (19.4 per cent). Jharkhand consistently ranks among the top three states in terms of prevalence of child marriage (Alam, 2023). The consequences are both immediate and long-term. Early marriage significantly heightens the risk of adolescent pregnancy and maternal mortality while perpetuating cycles of low educational attainment and intergenerational poverty. UNICEF estimates that India continues to account for at least 1.5 million child marriages annually, with Jharkhand contributing disproportionately to this burden (UNICEF, 2022).

Social fabric, and the historical context of child marriage

Jharkhand is characterized by its significant Adivasi population nearly 26 per cent residing in remote, forested, hilly areas with limited access to health and educational facilities and livelihood infrastructure. This geographical isolation, compounded by displacement due to mining and industrialization, has entrenched poverty. For many tribal families, child marriage is a way of warding off economic precarity and the threat of trafficking, while simultaneously reinforcing community norms that glorify early unions as the means to cultural continuity.

Dalits and Other Backward Classes (OBCs), who together constitute over 60 per cent of Jharkhand's population, remain vulnerable to both caste-based marginalization and economic deprivation. Among these groups, child marriage is not merely a gendered practice but a mechanism of social survival, with dowry system and the fear of young boys and girls developing inter-caste relationships accelerating the push toward early unions. Interventions often fail when they do not adequately address layered structural determinants such as this intersection of caste hierarchies with patriarchal control.

Interestingly, child marriage is not confined to marginalized castes alone in Jharkhand. The predicament of Radha Pandey from Koderma and other such cases are proof that even socially dominant groups are not immune. Moreover, the motivations differ significantly from neighbouring states such as Bihar and Uttar Pradesh, where upper-caste child marriages are often tied to dowry negotiations and consolidation of agrarian wealth. In Jharkhand, upper-caste families living in districts marked by economic stagnation, limited diversification of livelihoods, and inadequate educational opportunities for girls are found to be vulnerable to child marriage. This convergence of economic insecurity with entrenched patriarchal expectations shatters the shield of caste privilege against this practice.

What emerges, therefore, is a nuanced landscape where child marriage cannot be attributed to poverty alone. Instead, it reflects a complex interplay of historical

underdevelopment, displacement, caste stratification, and gendered anxieties that reinforce marriage as both a cultural imperative and an economic strategy. Recognizing these contextual variations is essential for designing interventions that are both culturally sensitive and structurally transformative.

Child marriage has little to do with large tribal population

The persistence of child marriage in Jharkhand is often misattributed to its large tribal population. Popular narratives and even policy discourses sometimes imply that high prevalence of child marriage is a cultural artefact of Adivasi life. However, district-level data reveals a far more complex reality, one that demands a deeper interrogation of Jharkhand's development trajectory and its persistent inequities.

Districts with very high Scheduled Tribe (ST) concentration Khunti (73.3 per cent), Simdega (70.8 per cent), Gumla (68.9 per cent), West Singhbhum (67.3 per cent), Lohardaga (56.9 per cent) and Latehar (45.5 per cent) often report *lower than average* prevalence, with Simdega recording the lowest rate (15.9 per cent) and Khunti just 21.7 per cent (NFHS-5). In contrast, districts such as Jamtara (50.5 per cent), Deoghar (49.2 per cent), Godda (48.5 per cent), and Giridih (45.6 per cent) where ST populations are moderate or low (ranging between 12-30 per cent) witness highest levels of child marriage in the state.

This inverse correlation shows that child marriage is not a "tribal issue" but a developmental crisis shaped by intersecting vulnerabilities. Tribal communities, while facing chronic disadvantages of remoteness, poor infrastructure and displacement, are not the sole or even the primary milieu of Jharkhand's child marriage crisis. Instead, the highest prevalence is found in districts where Dalits, OBCs and economically insecure upper-caste families struggle under the combined weight of dowry practices, patriarchal anxieties over inter-caste unions, and the lack of sustainable livelihood opportunities.

Field evidence suggests that child marriage and the fear of child traffickers can be related. In many marginalized communities, parents report arranging earlier marriages as a protective strategy against abduction, sexual violence, or trafficking a coping response where poverty, mobility and weak protection systems increase perceived risk. At the same time, child and forced marriages are often part of the trafficking process and other forms of exploitation: early marriages can create new vulnerabilities (including denial of schooling, economic dependence, and re-trafficking) and become counterproductive.

The plight of Jharkhand girl's children thus reflects the failure of a resource-rich state to protect the basic rights and opportunities of its citizens, leaving its most vulnerable Dalits, Adivasis, and the rural poor exposed to harmful practices that perpetuate cycles of poverty and disempowerment. This perspective is crucial for shifting the discourse from cultural blame game to developmental accountability.

Social background of trafficked children

Existing empirical evidence demonstrates that victims of trafficking disproportionately belong to Adivasi communities. Tribal girls constitute nearly 90 per cent of victims of trafficking from the state (Ram Dayal Munda Tribal Welfare Research Institute, cited in Outlook, August 2024). This overrepresentation is not incidental, but rooted in the intersecting dynamics of poverty, dispossession and systemic exclusion, as observed in Khunti district, where 73 per cent of the population is tribal and trafficking cases remain alarmingly common (The Hindu 2024). Dalit and OBC communities are also represented in these figures, though their numbers are smaller; studies note that vulnerabilities arising from caste-based hierarchies, land alienation, and lack of access to education intensify their susceptibility to trafficking networks (Srijan, 2020; Shaktivahini, 2018). Thus, trafficking in Jharkhand is best understood not merely as a law-and-order matter but as embedded in historical inequalities of caste and tribe, where marginalized groups bear the heaviest burden of exploitation (EPW Engage, 2019; Times of India, 2025).

Dropouts, Dowry, and the Burden of Honour

Education is widely recognized as the most effective safeguard against child marriage. Evidence demonstrates that girls who complete secondary education are significantly less likely to be married before the age of 18 (Paul et al., as cited in Alam, 2023). However, Jharkhand continues to face an alarming school-dropout rate. A recent survey released in Ranchi (August 2025) revealed that 38 per cent of children

had left school after experiencing verbal, physical, sexual or cyber violence, with girls and children with disabilities disproportionately affected (The Times of India, 2025). Such unsafe learning environments not only accelerate attrition but also heighten girls' vulnerability to early marriage.

Yet only increased access to school education won't suffice. Between 2019-20 and 2023-24, female literacy in Jharkhand increased from 64.1 per cent to 70.6 per cent. Yet these gains have not translated into economic empowerment. Female labour force participation remains strikingly low at 25.6 per cent, compared to 78.8 per cent for men. This mismatch sustains the perception that investment in girls' education yields limited returns, thereby reinforcing marriage as the default pathway for adolescent girls.

The practice of child marriage in Jharkhand is also deeply embedded in socio-economic realities. In low-income households, marrying daughters early is perceived as reducing financial strain. Dowry practices further incentivize early marriage, as younger brides are often associated with lower dowry demands. Field studies across Palamu, Garhwa, and Giridih highlight parental anxieties over inter-caste relationships, often resolved through hastened marriages (Alam, 2023). Underpinning these dynamics is patriarchal control over female sexuality, where marriage is construed as a means to safeguard "honour". Consequently, adolescent girls are seen as liabilities rather than as individuals with aspirations, and these cultural scripts, when intersecting with poverty, create powerful structural drivers of early marriage.

Confronting vulnerabilities

Jharkhand continues to be a critical source area for trafficking, particularly of minor girls coerced into domestic labour and sexual exploitation. In 2021, children accounted for 58 per cent of all trafficking victims in the state, with girls comprising nearly 60 per cent of them (The Times of India, 2021). Many of these victims were rescued from metropolitan cities such as Delhi, confirming the presence of organized networks that prey on the state's most marginalized communities. At the same time, expanding digital connectivity has created new forms of vulnerability. National Crime Records Bureau (NCRB) data indicates a sharp rise in cybercrimes against children, including online grooming and sexual exploitation (NCRB, 2022). Judicial consultations in Jharkhand have repeatedly highlighted the urgent need for digital literacy initiatives and the development of child-sensitive cyber-policing capacities.

Against this backdrop, judicial and policy engagement on child protection has intensified. The Juvenile Justice-cum-POCSO Committee of the High Court has convened state-level consultations, including the 2025 Stakeholders Consultation on Safeguarding the Girl Child, which brought together judges, policymakers, civil society actors and adolescent voices to collectively address systemic gaps (Live Law, 2025). Parallelly, the Department of Women, Child Development & Social Security has updated the State Action Plan (2025-2030), emphasizing strengthened roles for Child Marriage Prohibition Officers, convergence of departmental efforts, and intensified campaigns aimed at reshaping social norms (The Statesman, 2024). Legal innovations ranging from Child-

Friendly Police Stations to the Nirbhaya Shakti initiative and the National Legal Services Authority (NALSA) 2024 framework for child-friendly legal aid hold promise, though implementation remains uneven, particularly in rural and tribal districts.

But what is most inspiring is the agency of adolescent girls themselves. From Koderma to Ranchi, young leaders have not only resisted early marriage but also intervened in peers' cases and mobilized communities to challenge entrenched practices. Platforms such as *Bal Patrika*, supported by civil society actors, have amplified these voices, enabling adolescent girls to articulate aspirations that defy patriarchal constraints.

Multidimensional strategy to end child marriage

Jharkhand's recent State Action Plan to end child marriage represents a strategic shift towards comprehensive adolescent empowerment, with education positioned as its central pillar. The plan prioritizes universal access to free and quality secondary schooling for girls, supported by welfare interventions. These have contributed to a reduction in child marriages from 37.9 per cent (NFHS-4, 2015-16) to 32.2 per cent (NFHS-5, 2019-21) (The Times of India, 2021). These measures reflect an acknowledgement that delaying marriage is contingent upon ensuring that girls can pursue education without disruption, acquire financial literacy and access reproductive health knowledge, thereby developing the resilience necessary to resist the socio-economic imperatives of early marriage.

Parallel to educational strategies, Jharkhand is strengthening its legal framework in line with recent Supreme Court directives mandating the appointment of dedicated Child Marriage Prohibition Officers (CMPOs), the establishment of special courts, and the use of judicial injunctions under the Prohibition of Child Marriage Act (PCMA) (Hindustan Times, 2024; SCC Online, 2024; The Times of India, 2024). The state's draft Action Plan (2025-2030) underscores inter-departmental coordination, calling upon law enforcement and child protection agencies, and rural institutions to ensure stricter compliance and more timely prosecution. Simultaneously, community mobilization is to continue through campaigns such as *Bal Vivah Mukt Abhiyan,* communications to drive social-behaviour change, strengthening of Panchayati Raj Institution leadership, and reshaping entrenched gender norms by repositioning the value of the girl child (Jharkhand State News, 2024; The Times of India, 2024).

The plan also seeks to confront structural drivers by expanding economic and psychosocial support systems. Skill development initiatives and conditional cash transfers aim to alleviate the economic imperatives that often underpin child marriage practices (The Times of India, 2024). Investments in mental health infrastructure, including the Tele-MANAS helpline (accessible via toll-free number 14416 and operating through Central Institute of Psychiatry, Ranchi), further illustrate the state's commitment to integrating psychosocial counselling with adolescent health frameworks (Prabhat Khabar, 2024; News9live, 2024; Jagranjosh.com, 2024). Taken together, these layered interventions encompassing education, legal reform, community mobilization, livelihood security and psychosocial support aspire to construct a protective ecosystem in which adolescents can flourish holistically.

Policy pathways and the road ahead

Recent policy responses in Jharkhand reflect a discernible shift toward layered strategies that integrate financial incentives, legal reforms, and social norm change. Welfare schemes aimed at supporting adolescent girls, community campaigns against early marriage, and the integration of psychosocial interventions such as digital counselling platforms collectively signal a recognition that the problem of child marriage requires multi-pronged solutions (The Times of India, 2024; Prabhat Khabar, 2024). Yet, structural constraints remain significant. Uneven enforcement of the Prohibition of Child Marriage Act (PCMA), unsafe schooling environments, and the limited livelihood opportunities for young women continue to undermine the sustainability and effectiveness of these measures (Hindustan Times, 2024; SCC Online, 2024).

At the heart of the emerging solutions, however, are adolescent girls themselves. Increasingly, they resist early marriage, mobilize peers, and articulate their aspirations through grassroots platforms, exemplifying the transformative potential of adolescent agency (Alam, 2025). Jharkhand's pathway forward requires amplifying this agency while addressing structural vulnerabilities through coordinated, multi-sectoral action involving education, law enforcement, livelihood security, mental health, and community mobilization. Encouragingly, state leadership has demonstrated a consistent orientation toward safeguarding the rights of marginalized groups and Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), strengthening welfare provisions, and investing in inclusive growth (Jharkhand State News, 2024). If such momentum is sustained, Jharkhand could emerge as a model for curbing child marriage in India.

Conclusion

Jharkhand thus occupies a strategic inflection point. Alignment of judicial initiatives, state policies, civil society programmes, and adolescent leadership could position the state as a replicable model for high-prevalence regions nationwide. Achieving a child-marriage-free Jharkhand necessitates more than statutory prohibition; it requires dismantling structural inequities, expanding education and livelihood access, and reinforcing the courage of young women with protection, resources and justice. Supporting their agency will be decisive in building a more equitable and inclusive society.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

बी.एस.सी. मास कम्यूनिकेशन (3 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671 संतोष गुप्ता - 9755618891

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

दीनदयाल उपाध्याय
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

4.95 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते में

₹495.96 करोड़

आदान राशि अंतरित

बजट 2026-27 में **₹600 करोड़** का प्रावधान

भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जा रही **₹10,000 प्रति वर्ष** की आर्थिक सहायता

वर्ष 2025 में **5.62 लाख** से अधिक हितग्राहियों के खातों में **₹562.11 करोड़** से अधिक की राशि अंतरित

22,028 बैगा-गुनिया परिवारों को भी मिल रहा लाभ

R.O. No. 13763/1

साय सरकार में मेहनतकश हाथों को मिल रहा **संबल, सुरक्षा और सम्मान**

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

राज्य ग्रामीण
आजीविका मिशन-बिहान

छत्तीसगढ़ की लखपति दीदियां

संघर्ष से सम्मान तक, आगे बढ़ती बिहान की दीदियां

08 लाख
महिलाएं बनीं **लखपति दीदी**

10 लाख
अतिरिक्त महिलाओं को **लखपति दीदी** बनाने का लक्ष्य

₹05 करोड़ का **बजट प्रावधान**
लखपति दीदियों के व्यावसायिक अनुभव के विस्तार हेतु **लखपति दीदी भ्रमण योजना** की शुरुआत

2.8 लाख स्व-सहायता समूह और **30.85 लाख परिवार** बिहान मिशन से जुड़े

महिलाओं को **प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता** से बनाया जा रहा आर्थिक रूप से **सशक्त**

महिला समूहों को उद्यम के लिए बेहतर जगह उपलब्ध कराने **368 महतारी सदनों** का हो रहा निर्माण

R.O. No. 13763/1

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in